हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 1978

खंड 1 अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 6 मार्च, 1978

पष्ठसंख्या

तारांकित प्रश्न–एवं उत्तर (6)1

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

(6) 24

अतांराकित प्रश्न एवं उत्तर

(6) 35

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य.

(1) ध्यानाकर्षण सूचना सं0 12 व 5 के सम्बन्ध में

(6) 45

(2) ध्यानाकर्षण सूचना सं0 11 के सम्बन्ध में

(6) 51

वर्ष 1977–78 के लिये अनुपूरक अनुमान (दूसरी किश्त)

(1) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा (6) 56

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चची तथा मतदान (6) 59

वर्ष 1973– 74 के लिये अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें पर चर्चा तथा मतदान (6) 78

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 6 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ में 14.00 बजे हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहबान अब सवाल होंगे ।

The normal Tenure of chief engineer P.W.D.

***203. Chaudhry Partap Singh Thakran:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) Whether the Government has fixed normal tenure of five years for Chief Engineers in Public Works Department;

(b) if so, whether any of the Chief Engineer has crossed that period of normal tenure & if so, the reasons thereof; and

(c) whether any Chief Engineer is holding additional charge of the following posts: —

(i) Chief Architect,

(ii) Director of Technical Education,

(iii) Chief Engineer, Kurukshetra University,

(iv) Director Y.M.C.A. Institute Faridabad, If so, the reasons thereof ?

Irrigation and power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) Yes.

(b) Yes. Period of tenure of Chief Engineer FWD (B&R) has been crossed in public interest.

(c) (i) No.

(ii) Yes.

(iii) No.

(iv) No.

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सिविल सर्विसिज रूल्ज में टेन्योर का कोई प्रोसीजर है, यदि है तो क्या सिविल सर्विसिज रूल्ज को बदलने का इरादा है? अगर सरकार का बदलने का इरादा नही है तो इन रूल्ज को आज तक लागू क्यों नहीं किया गया?

श्री वीरेन्द्र सिंह : सिविल सर्विसिज रूल्ज में प्रोसीजर है और बदलने का अभी कोई विचार नहीं है ।

Distribution of Bhakra Canal Water

***250 Chaudhri Sant Kanwar** Will the Miniter for Irrigation and power be pleased to state the districtwise distribution of Bhakra Canal water in the State at present ?

Irrigation and power Minister (Shri Verender Singh) : Percentage distribution of Bhakra waters is as under:—

(i)	Karnal	3.26
(ii)	Jind	12.73%
(iii)	Ambala	0.82%
(iv)	Hissar	33.44%
(v)	Kurukshetra	18.54%
(vi)	Bhiwani	1.58%
(vii)	Sirsa	29.63%

श्री भले राम : क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट मे कोई भी परसेन्टेज नहीं रखी गयी, इसका क्या कारण है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह भाखडा वाटर की डिस्ट्रीव्यूशन का सवाल था । जो जिले इसमें कवर होते है उन की तो परसेन्टेज बतायी जा सकती है अन्य की कैसे बतायें?

Seats in the Hostel of Government College for Women, Rohtak.

***271 Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the Minister for Education be pleased to State—

(a) The Total number of seats in the hostel of Government College for Women Rohtak at present, together

with the number of seats actually required (so far); and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct some more rooms in the above said Hostel ?

Education Minister (Col.Rao Rain Singh) :

(a) No. of existing seats 94. Actual requirement 150.

(b) No.

चौधरी हरस्वरुप बूरा : मिनिस्टर महोदय ने सवाल के जवाब में बताया है कि अभी कमरे बनाने का कोई इरादा नहीं है तो मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो बाहर की लड़कियां दाखिल होती हैं उनको काफी दिक्कत होती है तो उनकी दिक्कत को देखते हुए कोई और अकमोडेशन का प्रबन्ध करेगें?

कर्नल राव राम सिंह : मैं अपने दोस्त से सहमत हूं कि इस वक्त वहां अकमोडेशन की दिक्कत है और इसी बेसिज पर प्रिंसिपल को गवर्नमैंट ने चिट्ठी लिखी है कि वह अपनी रिकमैन्डेशन जल्दी से जल्दी भेजे ताकि लड़कियों के होस्टल में कुछ और कमरे बनाने का प्रोग्राम बनाया जाये ।

New Buses Allocated to Jind Depot

*** 239 Chaudhri Ram Kishan:** will the Chief Minister be pleased to state the total number of new buses which are likely to be allocated to Jind Depot during the

current financial year 1977-78 ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) : 11 ।

श्री भले राम : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि गोहना डिपो में कुछ नयी बसें भेजने का इरादा है ?

श्री जगन नाथ : सारे डिपुओं में है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मुख्य संसदीय सचिव बताने का कष्ट करेंगे कि रोहतक डिपु में कितनी बसें देने का इरादा है?

श्री जगन नाथ : आप अलग से नोटिस दे दें, जवाब दे देंगे ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मुख्य संसदीय सचिव के नोटिस में यह बात है कि कुरुक्षेत्र जिले में तीस तीस सवारियां बसों की छतों पर बैठ कर जाती हैं, यदि है तो क्या वहां भी अधिक बसे भेजी जायेगी?

श्री जगन नाथ : यह ध्यान में है । हम ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां मंगा रहे हैं । सरकार सभी जिलों में बसें देगी ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मुख्य संसदीय सचिव जी बतायेगें कि अम्बाला जिले को भी नयी बसे मिलेगी या पुरानी ही चलती रहेगी?

श्री जगन नाथ : नयी भी मिलेगी और पुरानी भी चलती रहेंगी ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मुख्य संसदीय सचिव बतायेंगे कि जो बसें नयी आयेंगी उनकी बॉडी स्टील की बनवायेंगे या जैसे पहले प्लाई की बनती थी वैसी ही बनवायगे.

श्री जगन नाथ : स्टील की बनेगा ।

Price of Sugarcane

***285. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Irrigation and Power Minister be pleased to state—

(a) whether the State Government has discussed the matter with the Central Government for allowing resonable price of sugarcane to the cane growers ;

(b) If so, the price of sugarcane per quintal suggested by the State Government; and

(c) whether any suggestion has been made by the State Government to link the price of sugarcane with that of sugar ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) Yes.

(b) It was stressed that the statutory minimum cane price for the crushing season 1977-78 should not be less than Rs. 13/-per quintal.

(c) No.

चौधरी शिवराम वर्मा : : क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि जो गन्ने का भाव 13 रुपये है और सरकार ने कहा है कि 13 से कम नहीं मिलेगा । सरस्वती शूगर मिल 13 रुपये. से कम देने की कोशिश कर रहा है तो सरकार ने इसका क्या इन्तजाम किया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आपका सवाल है कि क्या राज्य सरकार ने गन्ने उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य दिलवाने के लिये भारत सरकार से विचार किया है? मैंने जवाब दिया है कि 13 रुपये के लिये हमने रिक्वैस्ट की थी परन्तु भारत सरकार ने अलग अलग जिलों में अलग अलग कीमतें फिक्स की हैं, हाइयेस्ट साढ़े नौ रुपये फिक्स की थी ।

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि अपनी तरफ से सरकार ने कितनी प्राइस फिक्स की है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : म्यूचअल एग्रीमेंट से सारे मिलों ने बौर शूगर कन्ट्रोल बोर्ड ने 13. 50 रुपये फिक्स की थी ।

चौधरी भजन लाल : मन्त्री महोदय ने तीन–चार दिन पहले यहां हाउस में बताया थाकि शूगर कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग बुलाई है और उसमें सरस्वती शूगर मिल के मालिक भी आये होंगे तो मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि जब कोआप्रेटिव शूगर मिल 13. 50 रुपये एक कविन्टल गन्ने की कीमत दे रहे हैं तो उन्होंने वह कीमत देने के लिये क्या फैसला लिया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : शुगर कन्ट्रोल बोर्ड की पहली तारीख को मीटिंग हुई थी जिसमें कोआप्रेटिव शूगर मिलों के मैनेजर आये थे । सरकार ने फैसला किया कि चाहे कोआप्रेटिव शूगर मिल को घाटा उठाना पडे लेकिन 13. 50 के हिसाब से गन्ना लें ।

जहां तक सरस्वती शूगर मिल का ताल्लूक है, उस दिन उनका रिप्रेजेन्टेटिव न आ सका क्योंकि उनके मालिक की बीबी को हार्ट अटैक हो गया था । जनरल मैनेजर भी बीमार था । परसों उनका रिप्रेजेन्टेटिव मिलने आया था । हमने उसको परसवेड किया कि वे 13. 50 रुपये के भाव से गन्ना ले । दों–तीन दिन में उनके री–एक्शन का पता चल जायेगा ।

श्री मूल चन्द जैन : मिनिस्टर साहब ने ''सी'' पार्ट के जवाब में बताया है कि चीनी की कीमत से गन्ने की कीमत को लिंक करने का भारत सरकार को सुझाव नहीं दिया । क्या मैं मिनिस्टर महोदय से यह जान सकता हूं कि हमारी सरकार ने यह सुझाव क्यों नही दिया कि शूगर की कीमत गन्ने की कीमत के साथ लिंक की जायें?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसे सरकार जरूरी नहीं समझती थी ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात है कि गन्ना 13 रुपये क्विंटल की बजाए 7– 8 रुपये

क्विटल भी लिया जा रहा है? यदि लिया जा रहा हए तो सरकार ने उसका क्या प्रबन्ध किया है?

श्री बीरेन्द्र सिंह : हमारे यहां हरियाणा में केवल चार शूगर मिल चल ये हैं और पांचवां बन्द है । चारों शूगर मिल 13. 50 रुपये दे ये हैं । शायद विज साहब खांडसारी यूनिट्स की बात कर रहे हैं ।

श्री हीरा नन्द आर्य : क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि गन्ने की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है? दूसरे क्या सरकार के नोटिस में यह बात है कि गन्ने से मंहगी उसकी पत्तियां बिकती हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कास्ट आफ प्रोडेक्शन सरकार के वेरीयस डिपार्टमैंटस या हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर्ज निकालते हैं । जो भी अधिक से अधिक निकालते हैं उसी के आधार पर हम भारत सरकार कौ रिकमैन्ड करते हैं कि मीनिमम प्राइस किसी फसल की कितनी होनी चाहिए लेकिन यह राज्य सरकार के नियन्त्रण में नहीं है लेकिन जो भी भारत सरकार मुकर्रर करती है वही कीमत हमें माननी पड़ेगी ।

श्री शमशेर सिंह : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा मसला है कि जिससे सरकार इन कीमतों को प्राइवेट मिलों और खांडसारी यूनिटस पर इन्फोर्स कर सके –या सरकार कोई और ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात लेना चाहती हो?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते । जो मीनिमम प्राइस फिक्स होती है उसको इन्फोर्स कर सकते हैं । लेकिन पिछले दिनों ऐ सा होता रहा है कि म्युचअल अन्डर–स्टैन्डिग से वे प्राइसिज मिलती रही हैं, कोई मसला खड़ा नहीं हु आ । दूसरे यह आल–इंडिया की प्रोब्लम है । सैन्टर से पूछेंगे कि म्युचअल दोनों पार्टियों में क्या एग्रीमैंट हुआ है । इस तरह से हम कैसे इन कीमतों को इन्फोर्स कर सकते हैं?

कंवर राम पाल सिंह : मन्त्री महोदय ने अभी यी बताया है कि हरियाणा के बाकी शूगर मिल तो साढ़े तेरह रुपये के हिसाब से गन्ना ले रहे हैं लेकिन सरस्वती शूगर मिल यह दाम नही दे रहा क्योंकि वह अभी केन–ग्रोअर्ज की स्ट्राईक की वजह से बन्द पड़ा है, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार उसको इस बात के लिये मजबूर नहीं कर सकती कि वह भी साढ़े तेरह रुपये गन्ने का भाव दे क्योंकि आपको याद हो गा पिछले दिनों में जब उसको घाटा होता था तो सरकार उसक्एरू घाटे को पूरा करने के लिये ग्रान्टें दिया करती थी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कानूनी तौर पर सरकार उसे मजबूर नहीं कर सकती ।

श्री देवी दास : जैसा मन्त्री महोदय ने बताया है कि हरियाणा के 5 मिलों में से एक मिल बन्द पड़ा है जिसकी वजह से किसानों को बहुत नुक्सान ह रहा हए, क्या सरकार इस बात

की कोशिश करेगी कि वह जल्दी से जल्दी इस मिल को खुलवाये और वह मिल किसानों को साढ़े तेरह. रुपये का भाव दे । (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कामरेड शंकर लाल : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि यमुनानगर का शुगर मिल क्यों बन्द पड़ा हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वह इसलिये बन्द पड़ा है क्योंकि जमींदार उनसे साढ़े तेरह रुपये गन्ने का भाव मांग रहे हैं लेकिन वह दे नहीं पा रहे हैं ।

चौधरी सन्त कंवर : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में जो कोआप्रेटिव शूगर मिल्क हैं, उन्होंने जितना गन्ना कान्टैरक्ट किया हुआ है, वह सारा गन्ना पेलेंगी? क्या उनके नोटिस में यह बात भी आयी है कि कोआप्रेटिव शूगर मिल्ज ने भी कम गन्ना पेलना शुरू कर दिया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . जितना गन्ना इस वक्त शुगर मिल्ज ने अपने जिम्मे पेलना लिया है, वह सारे का सारा गन्ना पेलेंगी ।

चौधरी गंगा राम : स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर शूगर मिल्ज के मालिकों ने हरियाणा सरकार के साथ एग्रीमैंट किया कि 1 3. 50 रुपये के भाव से गन्ना वह लेंगे, मैं मंत्री महोदय से यी पूछना चाहूंगा कि जिन" गर मिलों के मालिकों ने इस एग्रीमैंट का वायलेशन किया है, क्या उन मिलों के लाइसैंस कैंसिल नही किये जा सकते?

श्री वीरेन्द्र सिंह : उनके लाइसैंस कैंसिल तो गवर्नमैंट आफ इंडिया कर सकती है । यह जो एग्रीमैट आप मैन्शन कर रहे हैं, यह ओरल एग्रीमैंट था कोई लिखित एग्रीमैंट नहीं था ।

श्री ओम प्रकाश : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो गन्ना पेलने के लिये लेना है, यह बरसात से पहले ही ले लेंगे या बरसात के बाद भी लेते रहेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरा ख्याल यह है कि बरसात के बाद तो मिले चलेंगी नहीं । वैसे 30 जून तक सारा गन्ना ले लेंगी ।

स्वामी अग्निवेशः अभी हीरा नन्द आर्य जी ने यह पूछा था कि. गन्ने की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या आती है जिसके जवाब में मंत्री महोदय ने यह बताया है कि यूनिवर्सिटीज के प्रोफैसरों से पूछ कर सैंट्रल गवर्नमैंट को रिक्मैंड करते हैं कि आप इनको इतनी प्राईज दें, क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि वह कष्ट आफ प्रोडक्शन कितनी है जिसके आधार पर आपने अपनी रिकोमैंडेशन सैट्रल सरकार को दी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : उसकी एग्जैक्ट फिगर्ज तो अभी मेरे पास नहीं हैं लेकिन कोई 11– 12 रुपये तो जरूर होगी ।

स्वामी अग्निवेश : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको आपके द्वारा यह अर्ज करूंगा कि ये मुझे इस बारे में एग्जैक्ट फिगर्ज दे दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप मुझ से हाउस से बाहर ले लेना ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे. कि रू जो किसान यमुना नगर शूगर मिल में मिल बन्द होन की वजह से गन्ना रही दे पा रहे हैं और वे खांडसारी के लिये 7– 8 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, क्या उनको कोई सबसिडी देने का सरकार का विचार है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : सबसिडी देने का कोई विचार नहीं है ।

डाक्टर वृज मोहन गुप्ता : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो यमुना– नगर शूगररू मिल 3– 4 रोज से बन्द पड़ी है और वहां पर जमींदारों के धरने लगे हुए हैं और इमके साथ ही साथ वहां पर आज या कल से लेबर–ट्रबल. भीं– शुरू होने वाली है । क्योंकि वहां पर जो एम्पलाईज हैं, वह भी सीजनल होते हैं जिन्हें वे' रिटेनिंग अलाउन्स देकर भेज देते हैं, तो क्या इस बात को ध्यान रखते हुए कि वहां पर लेबर ट्रबल भी शुरू होने वाली है जोकि अगर शुरू ..होगयी तो. काफी. सीरियस हो जायेगी, सरकार इस शूगर मिल को जल्दी से जल्दी चलवाने की कोशिश करेगी ताकि जो काश्तकार. का नुक्सान ते रहा है वह भी न हो?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आपका सवाल क्या है?

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता : मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब यमुनानगर सरस्वती शूगर मिल में इस किस्म की हालत हो रही है और वहां के जो मिल मालिक हैं, . वह मुझे यह पता है कि जानबूझ कर मीटिंग में नहीं आयेंगे, जैसे कि मंत्री साहब. ने यह बताया है कि वह मिल मालिक इस मजबूरी की वजह से मीटिंग में नहीं आ सके और इस कारण वह उनसे बातचीत नही कर सके, मगर दो–एक दिन हुए उनका रिप्रेजैटेटिव यहां पर आया था मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि वे मीटिंग में आना ही नहीं चाहते, क्या सरकार उन्हे किसी न किसी प्रकार से मिल जल्दी से जल्दी चलाने के लिये मजबूर करेगी ताकि किसानों को नुक्सान न हो ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि कानूनी तौर पर हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि जो साढ़े तेरह रुपये की प्राईस है, वह किसानों को दे । जो स्टैचूअरी मिनिमम प्राईस है, उससे आधा पर वह गन्ना पेलने के लिये तैयार है

श्री फतेह चन्द विज : क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात आयी है कि कोआ– प्रेटिव सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर इसलिए गन्ना लेने में यह रुकावट डाल रहा है क्योंकि उनको लैवी की चीनी का दाम 40–50 रुपये कम मिलता है जिससे उनको घाटा हो रहा है? क्या यह बात भी उनके नोटिस में है कि पंजाब के मुकाबले हरियाणा में लैवी शूगर की प्राईस कम मिल रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह बात मेरे नोटिस में है कि पंजाब के मुकाबले हरियाणा में लैवी शूगर की प्राईस कम मिल रही है । इसके बारे में मैं जल्दी ही एक मीटिंग सैटर के मिनिस्टर श्री बरनाला साहब से करने वाला हू ।

चौधरी देस राज : जो फार्मर्ज का गन्ना पिछले 6– 6 दिनों से खेतों में पड़ा संड रहा है, क्या उसके लिये सरकार कोई कम्पनसेशन देने पर विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं समझा नहीं आपका सवाल?

चौधरी देस राज : मेरा कहने का मतलब यह है कि जो यमुनानगर सरस्वती शूगर मिल के एरिया का गन्ना खेतों में सड रहा है, उसको पर्ची भी मिल चुकी है, लेकिन वह ले नहीं रहे हैं, क्या सरकार उसके लिये कोई कम्पनसेशन देने पर विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : किसी ने सा कोई प्रार्थना पत्र भी तक दिया नहीं । ऐसा कोई प्रार्थना पत्र आयेगा तो फिर उस पर विकर कर लिया जायेगा ।

चौधरी हरि चन्द हूडा : मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि हमारी मजबूरी है हम कानूनी तौर पर उन्हें मजबूर नहीं कर सकते क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कानून किसानों को दुख देता है उसको बदलने की कोशिश की जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जी हां । जहां पहले दो हजार रुपया जुर्माने की सजा थी, वहां पर हम उसे बढ़ा कर एक साल की मिनिमम इम्प्रीजनमैंट भी कर रहे हैं ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात का पता है कि चीनी की रिकवरी पंजाब और यू 0 पी 0 के मुकाबले में हरियाणा में ज्यादा है और पंजाब और यू 0 पी 0 के किसान से गन्ना ज्यादा भाव पर लिया जाता है क्या वजह है कि सरकार हरियाणा के किसानों की परेशानी अभी तक दूर नहीं कर पायी है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . यू 0 पी 0 और पंजाब में गन्ने से चीनी की रिकवरी हरियाणा से ज्यादा है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मामला हए । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि करनाल, रोहतक और सोनीपत में क्या रिकवरी है और यमुना नगर में क्या रिकवरी है? मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि..

श्री अध्यक्ष : आप बताइये ननी, सवाल पूछिये ।

चौधरी भजन लाल : यहां पर यू 0 पी 0 के मुकाबले में, यमुनानगर सरस्वती शूगर मिल का एरिया यू 0 पी 0 के साथ लगता है. कोई ज्यादा अन्तररू नहीं है जबकि रोहतक, करनाल और सोनीपत में चीनी की मिकदार कम नहीं आती है लेकिन उनका गन्ना 8 और 9 रुपये क्विटल बिकता है । आपका' यह फर्ज

है कि यमुनानगर के एरिया के किसानों को भाव पूरा दिलवाये । जो आपने यह कहा कि पंजाब और यू 0 पी 0 की. रिकवरी हमारे से ज्यादा है और हमारी कम है, यह गलत बात है, कि पंजाब की रिकवरी हमारे से ज्यादा है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं मैम्बर साहब को चौलेन्ज करता हूं if he can quote any figure कि पंजाब की रिकवरी हमारे से कम है

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं इन्हें चौलेन्ज करता हूं । कोई भी मजा फाक्स कर लें । मैं इन्हें ठीक बता रहा है कि पंजाब की रिकवरी हमारे से कम है ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, मच्छी महोदय ने अपनी लाचारी जाहिर की है और उनके जवाब से जाहिर है कि मिल मालिकों से एग्रीमेन्ट का पालन करवाने में सरकार असमर्थ है । पिछली सरकार के जमाने में मिल मालिकों द्वारा एग्रीमेन्ट पूरे होते थे । क्या मंत्री महोदय बतांने की कृपा करेंगे कि क्या यह सरकार की नर्म पालिसी की वजह है कि मिल मालिक एग्रीमेन्ट का पालन नरी करते?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, पिछले सालों में यह एग्रीमेन्ट इसलिए पूरे होते थे कि शूगर की प्राईस कभी गिरी नहीं थी, हमेशा फायदा ही होता रहा । पिछले साल गन्ने का भाव 13 00 रुपए था और इस साल साढ़े तेरह रुपए का भाव हमने किक है । पिछले सालों में चीनी के भाव गिरे नहीं थे लेकिन इस बार

अचानक कीमतें गिर गई हैं इसलिए मिल वालो की कुछ हैसिटेशन हो सकती है ।

चौधरी शिवराम वर्मा : स्पीकर साहब? मेरे सवाल के 'सी' भाग का जवाब मन्त्री महोदय ने 'न' में दे दिया और फिर सप्लीमैन्टरी के जवाब में भी मन्त्री महोदय ने कह दिया कि 'इसकी जरूरत नहीं है । अगर चीनी के भाव के साथ गन्ने का भाव जोड़ दिया जाए यानी कि जब चीनी का भाव बढ़े तो गन्ने का भाव भी बढ़ जाए और जब चीनी का भाव गिरे तो गन्ने का भाव भी गिर जाए । अगर ऐसा कर दिया जाए तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए लेकिन मेरे सवाल के जवाब में मन्त्री महोदय ने 'न' कह दिया । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा करने में क्या दिक्कत है?

Shri Verender Singh: The hon. Member had asked.

(c) Whether any suggestion has been made by the State Government to link the price of sugarcane with that of sugar and I replied 'No'.

चौधरी शिवराम वर्मा : स्पीकर साहब, अगर चीनी की प्राईस से गन्ने का भाव जोड़ दिया जाए तो सारी समस्या हल हो सकती है । क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं ।

श्री वोरेन्द्र सिंह : आपने यह पूछा था कि क्या कोई सजेशन गवर्नमैंट आफ इंडिया को दी है और मैंने कहा. था 'नो'

। क्योंकि गन्ने की कीमत ठीक मिल रही थी । अगर अब कोई सुझाव होगा तो उस पर गौर किया जाएगा (व्यवधान.) ।

(इस समय कई सदस्य खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाईए Please take our seat क्या आप अब विचार करने को तैयार हैं ? What he wants to know is whether you are prepared to consider to suggestion now ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हां स्पीकर साहब, अगर अब यी सवाल आएगा तो हम विचार करने के लिए तैयार हैं ।

श्री गुलजार सिंह : स्पीकर साहब, जैसा बताया' 'गया है कि कओप्रेटिव शूगर मिल साढ़े तेरह रुपए के हिसाब से गन्ना खरीद रहे. हैं, यह तो ठीक है लेकिन 'पिछले कुछ दिनों से पेमेन्ट के बारे में काफी बेचौनी है । स्पीकर साहब, पता चला है कि पैमेन्ट जो की जा रही है वह ठीक नहीं की जा रही है और बैक भी पैसा नहीं' दे रहे हैं । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह की कोई सूचना मिंत्री है और अगर मिंत्री है तो क्या एक्शन लिया जा रहा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब ऐसी कोई इन्फरमेशन सरकार कुछों नहीं है (व्यवधान) । (इस समय चौधरी शिवराम वर्मा ने विना अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के बोलना शुरू किया)

Mr. Speaker: Please take your seat. You have to

follow the discipline.. You may please speak when you are called upon to do so. चौधरी पोसवाल साहब ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : स्पीकर साहब, आप जो चाहे' कहें लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं (हंसी)...

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : स्पीकर साहब, इसका मतलब यह हुआ कि चौधरी पढ़ा लिखा नहीं होता । यह बड़ा सीरयस मैटर. है (हंसी) । He should with draw it.

श्री अध्यक्ष : वैसे, डाक्टर साहब ठीक कह रहे हैं । Actally that is a slip of tongue.

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदय ने बतायों कि' हमारी रिकवरी कम है । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर यू0पी0 और पंजाब से हमारी रिकवरी कम है तो क्या उसी रेशो से हमारे किसानों को गन्ने की कीमत कम मिल रही हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : ' स्पीकर साहब, उस रेशो से तो कम नहीं मिल रही है । पिछले साल पंजाब में गन्ने की प्राईस काफी ज्यादा फिक्स हुई हैं । आज के दिन के मुकाबले पंजाब में गन्ने की रिकवरी ज्यादा है । लेकिन हम समझते हैं कि रिकवर्स के मुकाबले में वहां पर गन्ने की कीमत ज्यादा दी जा रही हैं ।

श्री जय नारायण : स्पीकर साहब, रोहतक शूगर मिल में जो गन्ना लिखवाया गया था उनके बोडो में से 40 परसेन्ट

गन्ना काटा जा रहा है क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इसके लिए कोई एक्शन लेने जा रहीं है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, सवाल तो कुछ और ही है । अगर हमारे पास किसी से शिकायत आएगी तो हम एक्शन लेंगे ।

श्री लहरी सिंह महरा : स्पीकररू साहब, मन्त्री महोदय ने बताया है कि हम मिल मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे मिल मालिकों को मजबूर नहीं कर सकते कि मिल मालिक 13. 50 रुपए के भाव से गन्ना लें जबकि उन्होंने पिछले सालों में लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कानूनी तौर पर हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते । मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं कि हम मिल मालिकों को मजबूर नहीं कर सकते ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब की इस बात को चौलेंज करता हू कि पंजाब की 'रिकवरी हुमारे से ज्यादा है । यह बिल्कुल गल्त बातू है । मैं आपको ठीक कहता हूं कि पंजाब की रिकवरी हमारे से ज्यादा नहीं है, कम है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आपको पिछली बातें याद होंगी । (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : . आर्डर प्लीज । चौधरी भजन लाल जी आप देखिए कि आप' एक सीनियर मैम्बर हैं और आपका बैठे–बैठे कहना ठीक नहीं है । आप खड़े होकर बताइए, आपको टाईम मिलेगा ।

चौधरी शिवराम वर्मा : स्पीकर साहब, गन्ने और चीनी की बात हाउस में चली हैं और सरकार भी परेशान है । मैं चाहता हूं कि अगर आधे घन्टे की डिस्कशन और हो ' जा0 तो ठीक रहे गा । आप आधे घन्टे की डिस्कशन का मौका दे दीजिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, काल अटेन्शन मोशन आया है और आज मैं जवाब दे रहा हूं (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष : आप इसके बारे में नोटिस दे दीजिए ।

Abubshehr Tourist Complex

***300. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state -

(a) the total amount invested and annual income accrued from Abubshehr (Sirsa District) Tourist complex ;

(b) whether any Project, report was got prepared from competent hands, before undertaking the construction to know the financial viability of the complex; if so, by whom ;

(c) whether the project as referred to in part (b) above is according to the priorities fixed by the Government

for expenditure on development works ; and

(d) the district-wise number of Tourist Complexes in the State together with their income and expenditure during the last financial year i.e. 1976-77 respectively ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) : The total amount invested so far is Rs. 70,000/- and no income has started accruing since the complex is only in initial stages of construction.

(b) Yes, the project report was prepared by the Tourism Department/Haryana Tourism Corporation.

(c) Yes.

(d) District-wise number of tourist complexes in the state is Gurgaon-7, Karnal-4. Ambala-4, Rohtak-2, Sonepat-1, Jind-1, Bhiwani-1, Hissar-1, Kurukshetra-1, Mohindergarh-2.

. As per tentative accounts for the year 1976-77, an expenditure to the tune of Rs. 210.03 lacs was incurred on running the tourist complexes and an income of Rs. 217.32 lacs was earned.

श्री देवेन्द्र शर्मा : मन्त्री महोदय ने सवाल के 'बी' पार्ट के उत्तर में कहा है, हां । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये टूरिस्ट काम्पलेक्सिज कमर्शियल बेसिज पर चल रहे हैं, वहां फायदा होगा या नुक्सान होगा?

कर्नल राव राम सिंह : हरियाणा टूरिज्म कार्पोरेशन और हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमैट के इस क्षेत्र में काफी एक्सपर्टस काम कर रहे हैं । उन एक्सपर्टस का अन्दाजा आप इस चीज से लगा सकते है कि यह डिपार्टमैंट दूसरे प्रान्तों को भी कंसलटेन्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है । यू 0 पी0 के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाए हए । यू 0 पी 0 में दूसरे प्रोजेक्ट भी चल रहे है जैसे नरौरा, आगरा तथा मथुरा । इनमें हम कंसलटेन्सी वर्क दे रहे है । बयाम प्रोजेक्ट तर तलवन्डी में और एच0 एम0 टी0 के लिए पिन्जौर में तथा बिजली निगम यू 0 पी0 में कंसलटेन्सी वर्क कर रहे है । जब दूसरे प्रान्त यह समझते हैं कि हरियाणा टूरिज्म मैं इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि उनके प्रोजेक्ट हम बनाएं, उनके प्रोग्राम हम चलाए तो हम अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूसरों को बाहर से बुलाएं यह कहा तक ठीक कुए इसे आप समझ सकते हैं ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो टूरिस्ट कम्पलेक्स बनाया गया है, उमके इर्द–गिर्द कोई आबादी है या कोई सड़क है, जो इस कम्पलेक्स को इस्तेमाल करेगी?

कर्नल राव राम सिंह : यह जरूरी बात है कि जब किसी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बनायी जाती है तो उसकी जरूरत देखी जाती है कि प्रोक्जेट बनने के बाद उस पर साल में कितना खर्च होगा और उससे कितनी आमदनी होगी । कितनी आबादी वहां पर है और वहां पर कितनी सड़कें हैं, कितने टूरिस्ट वहां पर रोज

गुजरेंगे, जो उसका इस्तेमाल करेंगे । एक तो यह प्वांयट आफ व्यू है कि जो राजस्थान से सड़क अबूबशहर होते हुए डबवाली जा रही है वह वहां से एक किलोमीटर दूर से गुजरती है । वह रोड स्टैरटेजिक रोड करार दे दी गयी' है जहां पर ट्रेफिक काफी तादाद में बढ़ने की उमीद है और बाकी भी आम पास, राजस्थान के एरियाज, पंजाब के खासकर, बड़े खुशहाल एरिया है वहां लोगों के पास काफी पैसा है–, अच्छी आमदनी है और उसमें हरियाणा टूरिजम डिपार्ट– मैन्ट हिस्सा बांट ले तो हर्ज की– कोई बात नही है । वायबिलिटी के लिहाज से वर्क आ0ट किया गया है कि प्रोजेक्ट के कम्पलीट होने के बाद, और चालू होने के बाद उस पर एक साल में 96 हजार रुपया इन्कम होगी और 84 हजार रुपया खर्च होगा । इसका मतलब यह होगा कि 12 हजार रुपये का प्रोफिट होगा, यानी प्रोजेक्ट वायबल है ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : जवाब के पार्ट 'सी ' में मैंने प्रापर्टी फिक्स करने के बारे में पूछा हे । तो इस लिये क्या मैं अपनी सरकार से पूछ सकता हूं कि हमारी सरकार तथा मुख्य मन्त्री महोदय ने जगह–जगह एलान किया है कि पानी, करप्शन, एग्रीकलचर रोडज को प्रायर्टी देंगे, तो क्या ये काम प्रायर्टी के मुताबिक हैं या कुछ लोगों के लिये कही सैरगाह तो नही बनायी जा रही ?

कर्नल राव राम सिंह : जो डिवेल्पमैंट की प्लेनज फिक्स की जाती हैं वह प्लेनिंग कमिशन, प्लेनिग डिपार्टमेंट फिक्स करता

है और उसके बाद प्लेनिंग कमिशन ने सोचकर जो ट्रिस्ट डिपार्टमैंट की डिवेल्पमैंट के लिये जो पैसा रखा, उस पैसे में टूरिस्ट डिपार्टमैंट ने जो कंडीगडंज मद्दे–नजर रखीं, उनमें तक कंडीशन तो सब से पहले वायबिलिटी की है, उसके बाद रीजनल इम्बेलेन्स दूर करने के लिये है । इस तरह हरेक जिले में एक टूरिस्ट कम्पलैक्स है लेकिन सिरमा डिस्ट्रक्ट में अब तक एक भी टूरिस कम्पलैक्स नहीं था इसलिये उस अबूबशहर वाले प्रोजेक्ट की वायबिलिटी छ्क तरफ रखी गयी और दूसरी तरफ रीजनल इंबेलेन्स दूर करने के लिये अबूबशहर को सिलेक्ट किया गया ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट से पहले एक प्रोजेक्ट वेस्टर्न व यमूना कैनाल के पाम बना था और वह पूरे हिमाचल को और जमुना पर पुलरू बनने के बाद यू0 पी0 को फीड करता है वह बहुत इम्पार्टेन्ट जगह है, यात्री बहुत आते हैं, क्या उसको अबूबशहर से जरूरी समझा गया या कम समझा गया?

कर्नल राव राम सिंह : पोसवाल साहब ने जो प्रोग्राम बनाया वह अच्छा होगा, अगर मैम्बर साहिबान अलग से नोटिस दें तो एक कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट उनके सामने रख देगें ।

लाला बलवन्त राय तायल : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस कंपंलेक्स पर कितना खर्चा आयेगा?

श्री अध्यक्ष : यह बता दिया गया है ।

लाला बलवन्त राय तायल : स्पीकर साहब, मेरा पूछने का मतलब यह है कि कुल इंवेस्टमैंट कितनी हे?

कर्नल राय राम सिंह : इम प्रोजेक्ट पर कुल 70 हजार रुपक खर्चे हो चुका है लेकिन जो डसका टोटल प्रोजेक्ट है, इवेस्टमैट है, उसके लिये माननीय सदस्य अलग से नोटिस दें तो मैं बता दूंगा । इस वक्त यह इफर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है ।

श्री फतेह चन्द बिज : मिनिस्टर साहब ने अबूबशहर कम्पलेक्स की आमदन और खर्चा भी बता दिया । क्या मिनिस्टर साहब बताने का कष्ट करेंगे कि बाकी जो कंपलेक्म हैं उन से 1975– 76 और 1976– 77 में कितना प्रोफिट हुआ?

कर्नल राव राम सिंह : मैं पहले ही डिस्ट्रिक्ट वाइज उन का ब्यौरा दे चुका हूं फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देता हूं कि उन सारे कंपलेक्म पर 210 लाख रुपये का खर्चा हुआ है और उन से 217 लाख रुपये की इंकम हुई है, मतलब कि 7 लाख रुपये का प्रोफिट हुआ है ।

कामरेड शंकर लाल : मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो अबूबशहर के अन्दर कंपलेक्स बनाया जा रहा है, वह वहां पर इन जिये तो नहीं बनाया जा रहा है कि वह चोटाला के नजदीक है जोकि हमारे चील मिनिस्टर साहब का गांव है?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, मेरा ख्याल है कि मेरे माननीय दोस्त शंकर लाल जी का गांव भी उमके नजदीक ही पड़ता है । कम से कम उनकी कास्टीचुएंसी तो नजदीक है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यी पूछना चाहता हूं कि टूरिजम डिपार्टमैंट के जो टूरिस्ट कम्पलेक्स हैं, इनकी परिभाषा क्या है? क्या एक रेस्टोरां बना देने से ही टूरिस्ट कम्पलेक्स पूरा हो जाता है? (शोर) । स्पीकर साहब, भिवानी में केवल एक टूरिस्ट डिपार्टमैंट का रेस्टोरां है क्या एक ही रेस्टोरां बना देने से पूरा टूरिस्ट कम्पलेक्स बन जाता है?.

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त का मत यह है कि पिछली सरकार ने भिवानी के अगेन्सट डिमक्रिमीनेशन की थी, इस से तो मैं सहमत नहीं हूं (हंसी) –

चौधरी खुरशीद अहमद : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह चीज है कि गुड़गांव में जो टू रिस्ट कम्पलेक्स बनाया गया है वहां पर इतनी ज्यादा. भीड़ होती है कि वहां पर बैठने के लिये जगह भी नहीं मिलती, क्या इस को मद्देनजर रखते हुए सरकार वहां पर दो चार टूरिस्ट कम्पलेक्स और खोलने का विचार रखती है ताकि लोगों को किसी प्रकार की तंगी न हो सके ।

(कोई उत्तर नही दिया गया)

चौधरी हरि चन्द हूडा : स्पीकर साहब, जों रोहतक मे टूरिस्ट कम्पलेक्स बनाया गया –है जो झील के पास है उसकी जमीन भी बहुत अच्छी है, प्रोडकटिव है, वहा पर उसको बदलने का सरकार का कोई विचार है क्योंकि पैदावार के इलावा यह कम्पलैक्स –बाबा मस्तराय की धार्मिक भूमि पर ही बनाया गया है ।

कर्नल राव राम सिंह : चौधरी साहब, रोहतक डिस्ट्रिक्ट तो वैसे ही लकी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर तो सारी जमीन ही बनिया है ।

श्री अध्यक्ष : वहां पर तो जरूरत ही नही है (हंसी) ।

कर्नल राव राम सिंह : वहां पर जो भी जमीन ली जाएगी, वह प्रोडक्टिव ही होगी ।

Linking Villages with Metalled Roads

***342. Shri Tek Ram :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) the policy of the Government at present to link each village of the State with the metalled roads together with the time by which the roads which are lying incomplete or on which the earth work has been done are likely to be completed ; and

(b) the total number of such villages in Mundhal Constituency which have not been linked with the metalled

roads together with the time by which these are likely to linked with the metalled roads ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) It is Governments policy to link every inhabited villages to a metalled road. It is not possible to indicate any time-schedule as the progress of the programme would depend upon the funds available.

(b) only one. It is expected to be linked up by end of September, 1978.

श्री टेक राम : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि मूढाल कांस्टीच्यूएसी के अन्दर जो तहसील बवानी खेडा है वहां जाने के लिये 5– 6 गांवों को 40 मील का चक्कर काट कर आना पड़ता है तो क्या मन्त्री महोदय कोई सीधी सड़क बनवा देंगे जिममे 4– 5 मील का फासला तह करके लोग जा सके?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अभी तो हरियाणा में बहुत ऐसे से गाव है जिनको सड़के नही मिंत्री हैं । इसलिये हर हल्के को चार चार सडके कैसे दी जा सकती हैं?

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि चिन सड़कों के गैप्स रहते हैं क्या वहां पर डुप्लीकेट रोड बनाने की कूपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह तो फंडज के पर निर्भर करता है ।

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय 1982 लच्छ यही कहते रहेगे कि फंडज पर मुनहसर है?'

श्री वीरेन्द्र सिंह : अभी तो 1978 ही चल रहा है अगले साल हाथ देखना ।

चौधरी सन्त कंवर : अध्यक्ष महोदय, परमो भी मन्त्री जी ने यही बताया था कि फंडज अवेलेबल होने पर सड़के बनाई जाएंगी । क्या मरकर को यह नहीं पता है कि फंडज कब तक मिल जाएंगे, क्या इनको बजट पर भरोसा नही है?

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, यह तो कोई सवाल न हूआ ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री साहब बनाने का कष्ट करेंगे कि मेरे हल्के में जौ बरेडी से बधोली तक का तीन मील का टुकड़ा है, उसको बनाने का कप्ट करेंगे?

(कोई उत्तर नही दिया नया)

श्री मूल चन्द मंगला : क्या। मन्त्री महोदय वताएंगे कि अगर किन्ही सड़कों पर गाय वाले मिट्टी डालने के लिये तैयार हों तो क्या वहां प्रायरिटी दी जाएगी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : जो गांव खुद मिट्टी डाल देंगे वहां अवश्य प्रायरिटी दी जाएगी ।

चौधरी गया लाल : क्या मन्त्री महोदय बताऐगे कि जिन सडकों पर मिट्टी 1972– 73 से डली डुई है उन सड्कों को अगले साल में बनाया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वह मिट्टी सरकार ने– डाली होगी, आपनें नही डाली होगी ।

चौधरी पीर चन्द : मन्त्री महोदय को पता होला कि रतिया हलके के साथ पंजाब की बड़ी बड़ी सड़के मिलती ऐं । इस हल्के को पंजाब की' भड्को के साथ मिलाने के लिये एक–एक मील के टुकड़े रहते हैं क्या उनको बनाया जाएगा?

श्री बीरेन्द्र सिंह : मैंने परसों भी अर्ज किया था कि 'ए' तथा 'बी' कैटेगिरी की जो सडकें हैं उनके लिये हम अगले माल पैसा खर्च कर रहे हैं ।

मास्टर शिव प्रसाद : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि अम्बाला शहर के जो गांव लिंक रोडज से नहीं मिले हैं वे इस साल जोड़ दिये जाएंगे?

श्री बीरेन्द्र सिंह : सारे गांवों का जुग्राफिया याद करना तो बड़ा मुश्किल है ।

चौधरी हरस्वरूप. बूरा : मन्त्री महोदय ने अभी 'ए' तथा 'बी' कैटेगिरी की सडकों का जिक्र किया रू मैं पूछना चाहता हूं कि 'ए' कैटेगिरी की कौन सी सडक होती है और 'बी'. की कौन सी होती है?

श्री अध्यक्ष : यह आप मन्त्री जी से अलग से पूछ लेना ।

श्री जब नारायण : मन्त्री महोदय को पता होगा कि हमारे इलाके में 10– 12 गांव ऐसे हैं जहां बारिश की वजह से वहां जाने के लिये 4–4 मील तक आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है तो क्या पहले ऐसे गांवों में सड़कें बनाने में प्रायरिटी देंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जितने भी मैरूड विलेजिज हैं वहां अगली बारिश से पहले जरूर सड़कें दे देंगे ।

Electric Meters

***336. Chaudri Des Raj :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether electric meters are not being supplied for new tubewell connections at present in the State ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : The tubewell connections are being released with installation of meters. But till 31-1-1978, in '928 cases; connections have been released without meters on account of shortage of meters.

चौधरी देस राज : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जहां पर मीटर नही दिया गया वहां पर पेमेंट का क्या आधार है?

श्री वीरेन्द्र सिह : पैडी एरिया के लिये तो एक दिन में 8 घंटे की औसत निकाली गई है और जो पैडी एरिया नहीं हैं उसके लिये आठ घंटे प्रति दिन की औसत निकालते है?

चौधरी देस 'राज : यह एवरेज इरीगेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है तो क्या सरकार इसको – कमकरने के लिये विचार रखती है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : हमारे पास इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आई है अगर आप कोई सुझाव देंगे तो हम बैठ कर बात कर लेगे ।

चौधरी ईश्वर सिह : स्पीकर साहब, जैसे कि सरकार बिजली के रेट फलैट रेट पर करने जा रही है तो फिर इन मीटरों का क्या करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जब फलैट रेट करेंगे तो लोगों से आक्शन लेते जो मीटर रखना चाहेगा रख सकेगा जो नहीं रखना चाहेगा उनके मीटरों को नीलाम ही करना पड़ेगा ।

कंवर राम पाल सिंह : जैसे मन्त्री महोदय ने पैडी एरिया' के हिसाब से निकाली गई औसत अभी बताई है तो इसके

हिसाब से लोगों को दूसरे सीजन में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा । क्या मन्त्री महोदय यह रेट सीजन के हिसाब से लेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर आप दूसरे सीजन के लिये इस रेट को अधिक समझते हैं तो हम बैठ कर बात कर लेगे ।

चाँधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो ट्यूबवैल्ज सामान के बगैर बेकार पड़े है उनको चलाया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कौन से ट्यूबवैलों की और कौन से सामान की आप बात कर रहे है ।

S.P. Posted at Karnal

***399. Lala Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the name of the S.P. posted at Karnal during emergency ;

(b) whether any complaints were received against him ;- and

(c) whether any enquiry was conducted or is being conducted on the complaints as referred to in part ;

(d) above ; if so; the stage thereof ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) :

(क) श्री वाई0 हरी शंकर, आई0पी0 एस0

(ख) हां ।

(ग) कुछ जांचें की जा चुकी हैं और अन्य की जा रही हैं । इनके बारे अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

लाला बलवन्त राय तायल : क्या मिनिस्टर साहब उस शिकायत को पढ़ कर सुनायेगे?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, यह एक लंबी लिस्ट है अगर आप कहें तो मैं सारी पड़ कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष : जो मोटी मोटी बाते हैं, आप बता दें बाकी इनको अलग से बता देना ।

Dr. Mangal Sein : Alright, Sir, Some of them are as under :—

(i) On an anonymous complaint received from a Social Worker to the Governor of Haryana, DIG/AR was asked to hold an enquiry. This complaint contains allegations of corruption against Karnal Police particularly Shri Y. Hari Shanker (formerly SP/Karnal). The following specific 'allegations were made :-

(a) He used to take monthly from all his SHOs especially from SIs Nand Kishore, Beant Singh, Jai Lal, Sunder Lal, Jaswant Singh and Inspector Rishi Parkash.

(b) While posted as SHO PS Sadar Panipat in Dec., 1974 SI Beant Singh destroyed a dead body and did not register the case of murder after taking Rs. 5000/- from the

accused party. Later on, an enquiry was held by DSP Jai Singh as also by Inspector. Chattar Singh on whose adverse report Shri Beant Singh was placed under suspension. Shri Shanker who used to call SI Beant Singh as his ‘Bara Bhai' manoeuvred the departmental enquiry in his favour, got him reinstated and again entrusted him the charge of SHO/PS City.Karnal.

(c) In 1975, ASI Baljit Singh and Inspector Ranjit Singh of CIA Staff, Karnal murdered a sikh r/o village Kulberi Tehsil and district Karnal. The enquiry conducted on this case was also got field by Shri Shankar because he used to take monthly from Inspector Ranjit Singh.

(d) In the year 1975-76 two murders were committed in village Padha Kohand of PS Gharaunda but Shri Sunder Lal, SHO did not register the-murder cases by taking Rs. 20000/- from the accused party with the connivance of Shri Shankar. Shri Chattar Singh, Inspector, conducted an enquiry into case and got the cases registered. Shri Sunder Lal, SHO was suspended but Shri Shankar tried to have a magisterial enquiry conducted in order to save him.

(e) In 1974, a sample was taken from Ahuja Petrol Pump, Panipat by Shri Jai Singh. DSP hut with the intervention of Shri Shankar, the sample was returned to the dealer. Slid Shanker is alleged to have taken Rs. 10000/- from the dealer. Similarly, in 191c, Kanwar Nirmal Sisgh, ASP/Karnal took a sample from a Petrol Pump at Karnal and in that case too the sample was returned at the instance of Shri Shankar who had taken a bribe from the concerned party.

स्पीकर साहब, यह तो बड़ी लम्बी लिस्ट है, इमको पढ्ने में बड़ा समय लगेगा । बाकी केसिज भी ऐसे ही है ।

लाला बलवन्त राय तायल : स्पीकर साहब, मेरे क्वैश्चन के जवाब में मुझे जो कागज दिए गए है उसमें कम्पलेन्टस की त्हापी नही दी गई, इसी लिए मैंने यह इन्फर्मेशन आपसे मांगी थी । इसके आगे मेरा सप्लीमैंटरी यह है कि इस केस की इन्क्वायरी कौन अफसर कर रहा है?

डाक्टर मंगल सैन : ये जौ 15 आक्षेप लगाए गए थे इनकी इक्वायरी डी 0 आई 0 जी0 अम्बाला रेंज को दो गई थी और इनकी रिपोर्ट वसूल हो जाने के बाद हमने यह इन्क्वायरी विजिलेंस को दे दी हए ।

चौधरी हरि चन्द हूडा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगें कि इनको री–इनस्टेट कर दिया गया है या नही?

डाक्टर मंगल सैन : री–इन्स्टेट हो रहे है लेकिन जांच चल रही है

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह एक बड़ा सीरियम मामला है । करनाल के एक श्री हरिराम हैं । पुलिम ने उनको मार–पीट कर टेप रिकार्ड करवाया है कि वह बंसी लाल को मरवाना चाहता है, उनके खिलाफ एक षडयन्त्र रच कर मुझे भी फंसाने की कोशिश की गई ताकि मेरी प्रतिष्ठा को गिराया जाये । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस षडयन्त्र में कौन कौन से

अफसर शामिल हैं और क्या उनके खिलाफ कोई कार्यबाही की है क्योंकि यह इन्कवारी बहुत दिनों से पैंडिंग पड़ी हे?

डाक्टर मंगल सैन : चौधरी भजन लाल जी ने हरिराम के बारे में ठीक प्रश्न पूछा हए । इनके बारे में स्पैशल इन्क्वायरी एजेंसी इन्क्वायरी कर रही है, बाकायदा इन्क्वायरी चल रही है ।

चौधरी सन्त कंवर : स्पीकर साहब, पिपली का एक केस था जिसके तहत वहां का जो एस0 पी 0 था उसके पर 302 का केस चल रहा है । सरकार ने अब उस को वहां से बदल कर चण्डीगढ मैं एक अच्छी पोस्ट पर लगा दिया है । यानी उसको गवर्नर का रार 0 डी 0 सी 0 लगा दिया है । यह आदमी इस केस में शामिल है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसको डस पोस्ट पर क्यों लगाया गया क्या यह यहां बैठकर इन्क्वायरी को इन्फलुएन्स नहीं करेगा?

डाक्टर मंगल : सैन यह प्रश्न रैलेवैंट नही है ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : क्या मिनिस्टर साहब फरमाएंगे कि जब डी0 आई0 जी0 की इक्वायरी हो चुकी थी तो दोबारा विजिलैस से इक्वायरी क्यों करवाई जा रही है? क्या गवर्नमैंट की तसल्ली नही थी जिसके कारण दोबारा इन्क्वायरी करवाई जा रही है?

डाक्टर मगल सैन : कुछ बाते ऐसी थीं जिनकी तसल्ली नही थी, इसीलिए इन्क्वायरी करवाई जा रही है ।

श्री लछमन सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इन एलीगेशन्ज के अन्दर यह एलीगेशन भी शामिल है जिसमें एस0 पी0 करनाल ने एक थाने के अन्दर एक खूबसूरत लडकी को बुलवा कर उससे शहर के चीदा लोगों केखिलाफ कहलवाया कि उसके साथ इन्होंने रेप किया है और जब श्री संजय गांधी करनाल में आए थे तो दो लाख रुपया इकट्ठा किया था?

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, ऐसा है, इस किसम की बातें नोटिस में है जिनकी इक्वायरी चल रही है । अगर भाई सुरेन्द्र सिंह जी जानना चाहते हैं तो वे अपने बापू से ही पूछ लें कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि यह बड़ा सीरियस केस है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं इसकी कौन आफिसर इन्कवायरी कर रहा है, किस स्टेज पर यह केस है और इसमें डिले का क्या कारण है?

डाक्टर मंगल सैन : चौधरी भजन लाल जी ने नाम पूछा है, उसका नाम है वाई0 हरि शंकर है । इक्वायरी इस समय किस स्टेज पर है, उसके बारे में मैंने अर्ज किया कि विजिलैस के सुपुर्द इक्वायरी की है । वहां कौन एस0 पी0 इन्यवायरी कर रहा है यह डिटेल की बात है । इस केस में डिले नहीं होगी । स्पीकर साहब, मैं हाउस को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गैर–कानूनी बाते कर रखी हैं, जुल्म कर रखे है, कानून की

जुरिस्डिक्शन से बाहर जा कर अपने स्वार्थ के लिए लोगों पर जुल्म कर रखे हैं, सस्कार उनको हरगिज माफ नहीं करेगी ।

चौधरी प्रताप सिंह ठाकरान : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त ये षडयन्त्र हो रहे थे उस वक्त होम मिनिस्टर कौन थे? (हंसी) ।

डाक्टर मंगल सैन : पोसवाल जी होंगे (व्यवधान) अगर इनकी कनाइवेंस से ये षडयन्त्र हुए हैं, यह मैं नहीं कहूंगा, it is too much (व्यवधान) ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मन्त्री महोदय बताऐंगे कि इस पुलिस अफसर के खिलाफ डी0 आई0 जी0 अम्बाला रेंज ने जब इन्यवायरी की थी तो उस वक्त वह सस्पैड था और अब इक्वायरी के बाद उस मे वजन पाया गया तो उसकी इन्क्वायरी विजिलेंस के सपुर्द करदी और उस वजन के कारण उसको बहाल कर दिया', इसका क्या कारण है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कंवर राम पाल सिंह : डी0 आई0 जी0 अम्बाला रेंज ने इक्वायरी की और रिपोर्ट दी । इसके बाद यह इन्यवायरी विजिलैस को दे दी है । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ जितने केसिज थे, क्या वे सारे के सारे विजिलैस को भेज दिए हैं या कुछ भेजे है? अगर कुछ भेजे हैं तो क्या उन केसिज में कोई एक्शन हुआ है जो पहली इक्वायरी से पूर्व हो गए है?

डाक्टर मंगल' सैन : और भी इल्जाम आ रहे हैं, सब की इक्वायरी विजिलैस को दे रखी है ।

चौधरी गंगा राम : . जिस समय करनाल में पूथ कांग्रेस वाले ड्रेन खोद रहे थे ओं उस समय सुरेन्द्र सिंह उस कैम्प के इन्चार्ज थे और एस0 पी0 श्री शंकर थे । इन्होंने 17 हजार रुपये की शराब यूथ कांग्रेस वालों को पिलाई । क्या मन्त्री महोदय इसकी इन्क्वायरी करवाएंगे? (व्यवधान एव शोर)

Mr. Speaker : Irrelevant.

श्री सुरेन्द्र सिंह : ये अपनी बात पूछते हैं नाम बदल कर... (व्यवधान) ।

डाक्टर मंगल सैन : अगर उस अफसर के खिलाफ कोई कम्पलेंट लाएंगे कि उसने इन के साथ मिलकर ऐसे गुनाह करवाए हैं तो जरूर इक्वायरी करेंगे ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : मैं वजीर साहब की स्टेटमैंट को चौलेंज नही करना चाहता हूं लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के वाईसचांसलर ने यूनिवर्सिटी में जो धांधली मचाई थी, जुल्म किये थे, उसके खिलाफ सरकार ने इक्वायरी क्यों नहीं की? उसको प्रोटैक्ट क्यों किया?

डाक्टर मंगल सैन : यहां पर वाई0 शंकर का किस्सा चल रहा है, बाईस चांसलर का किस्सा नही चल रहा । (व्यवधान)

लाला बलवन्त राय तायल : क्या मन्त्री महोदय बताएंमें कि करनाल में एमरजैसी डे क में यही एस0 पी 0 था?

डाक्टर मंगल सैन हां, यहीं लगा हुआ था । सुखदेव प्रसाद डिप्टी कमिश्नर थे और एस0 पी0 श्री वाई0 शंकर थे । यही लोग थे जब हम करनाल जेल में थे ।

लाला बलवन्त राय तायल : जब यह एमरजैसीडेज में करनाल मे एस 0 पी0 थे तो क्या उन दिनों किसी पुलिटिकल सफर को थाने के अन्दर पीटा गया था?

डाक्टर मंगल सैन : ठीक है, चौधरी सूरजमल को पीटा था, इस केस की जांच ही नहीं हो रही बल्कि इसके बारे में सदन को कहना चाहता हूं कि इक्वायरी कम्पलीट है और जिस अधिकारी ने पीटा है उसको चार्ज शीट कर दिया गया है ।

Income Derived by the Haryana Roadways

***348. Rao Dalip Singh :** Will the Chief Minister be pleased to **sate** -

(a) the total income derived by the Haryana Roadways, from the shops and vends on the Bus stands in the State during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 to-date.

(b) whether the prices of the articles sold on the shops and vends at the Bus stands in the State are fixed by the Department of being charged arbitrarily by the shopkeepers ; and

(c) whether there is any quality control on the articles sold at the Bus Stands.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) :

(क) 1975–76. 1976–77 1977– 78

29,48,782.10 39,9609.10 41,23,562.17

(ख) वस्तुओ के मूल्य उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनाई गई जिला लैवल मूल्य नियंत्रण कमेटी द्वारा नियतु किए जाते हैं । इन कमेटियों का कार्य खाद्य पदार्थो के मूल्य क्वालिटी वजन नियत करना और यह–देखना कि यात्रियो को अच्छी प्रकार की वस्तुऐं उपलब्ध हों, होता है ।

श्री हीरानन्द आर्य : क्या मंत्री जी बताएगे कि 1977–78 के मुकाबले मे 1975– 76 में और 1976–77 में प्रौफिट कम क्यों था?

श्री जगन नाथ : इसके लिए तो पिछली सरकार जिम्मेवार है । 1977– 78 की फिगर्ज हमारे टाईम की हैं । जहां भ्रष्टाचार हौ वहा प्रौफिट की बात हो नहीं सकती । पिछली सरकार कितनी भ्रष्टाचार थी इस बात को आप सब जानते हैं ।

राव दलीप सिंह : क्या मन्त्री जी बताएगे कि इन दुकानों पर जो बिला स्टैन्डर्ड चीजे बिकती हैं उनकी जांच करवाई जाएगी?

श्री जगन नाथ : उसकी समय समय पर जांच होती रहती है लेकिन अगर कोई शिकायत मैम्बर साहब के नोटिस में हो तो वे हमें बता दें, शाम तक दूर कर देंगे ।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर ।

Work Charged Employees

***382 Shri Ran Singh Maan :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services of work-charge employees at present working in the P. W . D . (B&R) ; and

(b) if so, the steps being contemplated in this regard ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) Yes.

(b) (i) A proposal to make work charged employees having 5 years continuous service or more as on 1-4-1975, regular is under consideration of Government work

(ii) Data in respect of work charged employees having 5 years continuous service or more as on 1-1-1978 is being collected from the field and the proposal to make them regular will he considered by the Government on the basis or the data collected.

Remarks in the A.C.R.

***448 Doctor Brij Mohan Gupta :** Will the Minister for the Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that in the beginning the overall assessment of the work of an official as an 'Average' were not considered as an adverse remarks ;

(b) if so, when an amendment was made and the 'Average' remarks were started to be considered an adverse remarks ;

(c) whether it is also a fact that retrospective effect was given to these orders, and due to their orders, many employees were given retirement at the age of 5') or 55 years ; and

(d) if so, the total number of persons of Irrigation and P.W.D. (B&R) were retired under these, orders at the age of 50 or 55 years separately

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(ए) जी हां, स्थिति अब भी यह है कि "Average assessment" को प्रतिकूल नहीं समझा जाता ।

(बी तथा सी) 55 वर्ष की आयु के पश्चात् सरकारी कर्मचारियो को सेवा में रखने के लिए संयुक्त पंजाब के परिपत्र क्रंमाक– 4776–3 जी0 एस0 (1)6 / 15023 दिनांक 1 9–2 1 मई, 1964 में यह व्यवस्था थी कि जिस कर्मचारी कं सेवा रिकार्ड Average (या better) हो उसे 55 वर्ष की आयु पर रिटायर न किया जाये बल्कि 55 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में रखा जाये । हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रंमाक 4449–2 जी0 एस0– 68 / 22951 दिनांक 3 सितम्बर, 1968 में यह निर्णय किया गया कि केवल उन्ही कर्मचारियों को जिसका सेवा रिकार्ड good या better अर्थात average से पर हो 55 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में रखा जाये और जिनका रिकार्ड average हो उन्हें सेवा में रहने की अनुमति न दी जाये । तदानुसार संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र दिनांक 19– 21 मई, 1964 में जहां शब्द average था उसे शब्द good से substitute कर दिया गया ।

दिनांक 24–9–1974 को यह हिदायते जारी की गईं कि समय–समय पर जो हिदायतें राज्य सरकार द्वारा सरकारी– कर्मचारियों कौ 55 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में रखने बारे जारी की हुई हैं वे 50 वर्ष की कि आयु के बाद राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को सेवा मैं रखने बारे भी लागू होगी ।

(डी) इन हिदायतों के अनुसार 50–55 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत किये गये क्लास 1 तथा क्लास 2 अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :–

विभाग का नाम	50–55 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत हुए अधिकारी		जोड़
	कलास–1	कलास–2	
सिंचाई विभाग	शून्य	1	1
भवन तथा सड़क विभाग	2	2	4

Upgradation of Schools

***361. Kanwar Ram Pal Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade schools during the next financial year ; and

(b) if so, category-wise number thereof and the criteria being adopted ?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(ए) जी हां ।

(बी) मामला विचाराधीन है । स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए जनसंख्या, छात्र– संख्या भवन, वर्तमान स्कूलों से दूरी इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है । प्राथमिक स्कूलों, कन्या स्कूलों तथा ग्रामीण/पिछडे क्षेत्र में स्थित स्कूलों का स्तर बढाने बारे विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

Haryana Bhawan

***366. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date on which the Haryana Bhawan, Delhi was constructed together with the cost incurred on its building and furnishing it separately.

(b) the year wise annual expenditure incurred on the maintenance of Haryana Bhawan and the year-wise annual income accrued therefrom during the last five years, separately ; and

(c) the manner in which the Rent of rooms is charged in Haryana Bhawan and whether the rates of rent are different for the different categories of persons ; if so, the details thereof ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Statement containing the required information is placed on the Table of House.

STATEMENT

(a) The Haryana Bhawan at Delhi was constructed

in July, 1970. The following expenses were incurred on its building and furnishing it :—

(i) Expenditure on building work Rs. 32,38,019.00

(ii) Expenditure on furnishing Rs. 4,57,037.00

(b) The year-wise expenditure on maintenance of Haryana Bhawan and income derived during the last five years is as under:—

Sr. No.	Year	Expenditure	Income
	1972-73	4,33,895.00	36,503.00
	1973-74	4,03,457.00	38,816.00
	1974-75	5,13,440.00	47,820.00
	1975-76	5,68,904.00	56,974.00
	1976-77	6,28,651.00	53,254.00

(c) The rates of rent being charged from different categories of persons for occupation of rooms in Haryana Bhawan are as under:-

Chief Minister's Ministe r's Suites. Rs.	Minister's Suites Rs. P.	Ordinary Suites (Single) Rs. P.	A. C. Suites (Single) Rs. P.
	2	3	4

P.

1

1.	Chief Minister	12.00	—	—	-
2.	Ministers/Deputy Ministers/ Speaker/ .Deputy Speaker/ Chief Parliamentary Secretary.	—	10.00	8.00	8.00
3.	(i) M. Ps./ M.L.As. of Haryana. Non-official members of Advisory Committees constituted by Government while staying in connection with meetings only		—	5.00	9.00
	(ii) Former Chief Minister of Haryana.	—	—	5,00	9.00

4.	Haryana Government officers on duty/ recepients of Padma Awards.	—	—	2.00	6.00
5.	Haryana Government Officers on leave or Haryana Government officers with Headquarters in Delhi.	—	—	4.00	10.00
6.	Officers of the Govern- meat of India, posted in Haryana while on duty (under rule F.R. 45-A)	—	—	12.00	18.00
7.	Others/non-official members of	—	—	25.00	40.00

	advisory Committees constituted by Government while not staying in connection with meetings.				
8.	Members of the family of an M.P./M.L.A. and of an officer of Haryana Government. (The word family is defined in rule 2.17 of CSR Vol. I, Part I)	—	—	4.00	10.00
9.	(i) Haryana Govern- ment officers on deputation :-				

(a) Those drawing TA/DA on same rates as Haryana Govt. Officers				
1. n duty	—	—	2.00	6.00
2. n leave	—	—	4.00	10.00
(b) Those drawing TA/DA at higher rates on duty or on leave.	—	—	4.00	10.00
(ii) Chairman, Manager Directors, General Managers, Secretaries, Technical officers &				

Other Officers of equivalent ranks of Government Corporations/ Boards/Autonomous Bodies, drawing TA/ DA at Govt. rates:—	
(i) While on duty	(i) As for Haryana Govt, officers on duty.
(ii) While not on duty	(ii) As for Haryana Govt. officers on leave.
(iii) hairman, Managing Directors, General Managers, Secretaries, Technical Officers & Other Officers or	As for Haryana Govt. officers on leave.

equivalent ranks of Govt. Corporations/ Boards/Autonomous Bodies, drawing TA/ DA/at rates higher than the Govt. rates whether on duty or on leave.	
Use of Committee Room for non-official meetings.	20.00 per day
Use of Dinning Hall & Lounge for non-official meetings.	50.00 per day
Telephone	1 .00 per day

	charges for local private calls from Haryna Government officers whether on duty or on leave.	
	Private S.T.D. & trunk calls from Haryana Govt. officers.	Full charges.
14.	Any person, otherthan Haryana Govt. officer, or local S.T.D. & trunk calls whether private or officials.	Full charges

Note:— The charges for a double suite occupied by Ministers/ Deputy Ministers/Speaker/Deputy Speaker/Chief Parliamentary Secretary will be as for a single suite.

2. When an air-conditioned suite is reserved for

an officer, he shall be required to pay charges fixed for air-conditioned suite, whether air-conditioner is used or not.

3. Rent from officer of the Government of India and of other State Govts. and Corporations, and other similar organisations will be charged on the basis of reciprocal arrangements, if any, made with them.

The following category of persons are also allowed the use of Haryana Bhawan on the payment of the charges shown against them:—

1.	Vice Chancellors and other officers of the Agricultural University, Hissar, the Kurukshetra University and officers of the Haryana State Electricity Board.	Allowed reservation in the same manner as officers of the Haryana Govt. if comparable rank and or payment of similar charges on reciprocal basis.
2.	Vice Chancellor and Registrar of the Punjab University .	—do-
3.	Orgainising Secretary, Joint Organising Secretary, & Deputy Secretary of the Indian Red Cross Society and the Haryana State Branch, while on official duty.	On same terms and conditions as are applicable to officers of Haryana Govern-went.

4.	Officers of the Civil Aviation Clubs in Haryana.	
	Chief Pilot Instructor	
	Chief Engineer	
	Air Craft Radio Engineer	
	Asstt. Pilot Instructor	
	Asstt. Engineer	
	Gliding Engineer	
(i)	Those drawing TA/DA at the same rates as Haryana Govt. officers.	
a)	on duty	(a) As for Haryana Govt. officer while on duty.
b)	on leave	(b) As for Haryana Govt. officer on leave.
ii)	Those drawing TA/DA at higher rates than Haryana Government officers.	
	(a) While on duty	(a) As per Haryana Govt. officers onleave.
	(b) While on leave	(b) At double the rates for Haryana Government

		officers while on leave.
5.	Officers on the Indian Oil Corporation who are exclusively concerned with the State of Haryana.	On the payment of same charges as are payable by the officers of Govt. of India.
6.	The recipients of Param Vir Chakra and Mahavir Chakra belonging to Haryana. In case of posthumous awards the recieptients who received the award on behalf of the deceased (for example wife, mother father) for a period not exceeding 10 days.	Same charges as payable by the officers of Haryana Government.
7.	I.A.S. Probationers. alloted to Haryana State while on Study Tour.	On payment of same charges as are payable by officers of Government of Haryana.

Besides some individual by designation are also entitled for use of Haryana Bhawan on payment of same charges as are payable by the officers of Govt . of Haryana. The list is as under :—

Individuals by designation.

1	Vice Chairman, Y.M.CA . Institute of Engineering, Faridabad.	On payment of same charges as are payable by the officers of the Government of Haryana.
.	Director, Y.M.C.A. Institute of Engineering, Faridabad.	On payment of same charges as are payable by the officer of the Government of Haryana .
.	Commissioner of Income Tax, Rohtak, Haryana.	To be charged the same rates as are payable by Haryana Government officers.
.	The Chairman, Beas and Bhakra Management Board.	—do-
.	The Chief Commissioner, Union Terriotory, Chandi-garh.	—do—
.	Accountant General and Deputy Accountant General, Haryana.	—do—

Scarcity of Drinking water in Ambala City

5

***44 . Master Shiv Parshad :** Will the Minister for

Irrigation & Power be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that there is much scarcity of drinking water in Ambala City ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the scarcity of drinking water in Ambala City ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) हां ।

(बी) हां ।

Pay Scales to the 15 per cent quota of the Headmasters

***420. Shri Bhale Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Principals of Higher Secondary Schools are being given the pay scale of Rs. 700-1600;

(b) whether the Government has fixed 15% quota of this grade of Rs. 700-1600 for Headmasters of Government High Schools; and

(c) whether the aforesaid pay scale mentioned in part (b) above being given to the Headmasters; if not, the reasons thereof ?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) :

(क) नहीं ।

(ख) और (ग) :– (क) भाग में दिए गए उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न पैदा ही नही होता ।

Strikes held in the Industrial Units

***432. Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the number of Industrial Units in which strikes were held during the period from the month of July, 1977 to date together with the number of units in which the strikes were declared unlawful;

(b) the number of times and the name of the Industrial Units in

which the Lathi charges were made together with the number of Labourers injured alongwith the number of labourers who were retrenched and names of units from which retrenchment was made ; and

(c) the position at present of the dispute which occured in Haryana Dyes Industries at Dhudeke, Bahalgarh and Sonepat together-with the action taken by the Government in the interest of Labourers ?

**** Interim Reply**

अ 0स0 पत्र0 क्र0 13(18

)–78/

मन्त्री

सतबीर सिंह मलिक वित्त विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।

दिनांक, मार्च 3, 1978

विषय – तारांकित विधान सभा प्रश्न 432

प्रिय,

कृपया उपरोक्त विषय पर उद्योग मंत्री., हरियाणा के निजी सचिव के अशा0 क्रमांक 1625– 1 आई0 बी0 (1)–78 दिनांक 2–3–78 जो कि सचिव हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित है, की ओर ध्यान दें ।

2. उपरोक्त प्रश्न श्रम विभाग को कल दिनांक 2–3–78 शाम को लगभग 4– 30 बजे उद्योग विभाग ने ट्रान्सफर किया था । विधल सभा की कार्य सूची अनुसार उक्त प्रश्न दिनांक 6–3–78 को विधान सभा में उत्तर के लिए देय हैं । इस का उत्तर देने बारे श्रम तथा पुलिस विभागों से सूचना अभी एकत्र नहीं हो सकी है । अपेक्षित सूचना एकत करने में कुछ समय लग जाने की सम्मभावना है । मैं आभारी हूंगा यदि आप उक्त प्रश्न का उत्तर देने में 7 दिन की एक्सटैन्शन प्रदान करेगें ।

आदर सहित

आपका

हस्ता/–

(सतबीर सिंह मलिक)

ब्रिगेडियर रण सिंह

आदरणीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा,

चण्डीगढ ।

Lining Work of Fatehabad Branch

***421. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the time **by** which the lining work of Fatehabad Branch will be started togetherwith the time by which it is likely to be completed ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : फतेहाबाद ब्रांच को पक्का करने के कार्य को वित्तीय वर्ष 1978–79 से आरम्भ करने तथा इसे तीन वर्ष के समय में पूर्ण करने की आशा है ।

Employment to Physically Handicapped

***449. Sint. Shakuntla Bhagwaria :** Will the Minister for Social Welfare be pleased to state the policy of the Government for providing employment to physically handicapped togetherwith the steps taken by the Government

in this respect ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(ए) विकलांगों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार के प्रत्येक रोजगार कार्यालय में एक विशेष सैल की स्थापना की है ।

(बी) भारत सरकार की सिफारिशो पर ऐसे व्यक्तियो के लिए सरकारी कार्यालयों में श्रेणी 3 तथा 4 के 3 प्रतिशत पदों के आरक्षण का प्रश्न राज्य सरकार 'के विचाराधीन है ।

Election to Municipal Committee

***428 Fateh Chand Vij :** Will the Minister for industries be

pleased to. state whether the Government has taken any decision to hold elections of Municipal Committees in the State : if so, the time by which the elections will be held ?

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मंगल सैन) : हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, 19 जुलाई, 277(3) में की गई ब्यवस्था अनुसार सभी नगरपालिकाओं के निर्वाचन की धारा 1938 से पूर्व करवाने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

J.B.T. Classes

54. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for

Education be. pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to restart the J.B.T. classes in the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid classes are likely to be started ?

Education 'Minister (Col. Rao Ram Singh)

(a) Proposal regarding the restarting of Diploma in Education (JBT) Classes is under consideration of the Government.

(b) Classes will be started if the proposal is ultimately approved by the Government.

Notified Area Committees in the State

M. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the number of Notified Area Committees in the State at present together with the steps taken by the Government to develop these committees ; and

(b) tha number of the Committees out of those referred to in part (a) above which are resourceful together with the funds allocated by the Government to develop the resourceless committees?

उद्योग मन्त्री (डाक्टर मगल सैन) :

(क) 45 अधिसूचित क्षेत्र समितियों के सीमित साधन होने के कारण उनके क्षेत्रो में सुधार करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है । उपलब्ध फन्ड की दृष्टि में सरकार हररू वर्ष अधिसूचित क्षेत्र समितियों को ऋण/अनुदान स्वीकृति करती है ।

(ख) अधिकांश अधिसूचित क्षेत्र समितियों की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ नही है कि साधन वाली तथा साधन रहित कमेटीज में कोई विशेष रेखा कायम की जा सके ।

वित्तीय साधनों की कमी होने के कारण यह सम्भव नही है कि सरकार प्रति वर्ष सभी अधिसूचित क्षेत्र समितियों को ऋण अथवा अनुदान स्वीकृत कर सके । तथापि अधिसूचित क्षेत्र समितियो के आय के साधनों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा यह भरसक प्रयत्न किया जाता है कि स्वीकृत बजट व्यवस्था अनुसार अधिक से अधिक अधिसूचित क्षेत्र समितियों को अनुदान स्वीकृत किया जाये । इस सिद्धात को ऋण स्वीकृत करते समय भी ध्यान में रखा जाता है । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण केवल उन्ही नगरपालिकाओं को बजट व्यवस्था अनुसार स्वीकृत किया जाता है जो कि सरकार को ऋण के लिए आवेदन पत्र देती हैं । इसके साथ ही सरकार द्वारा नगरपालिकाओं पर इस बात पर भी बल दिया जाता है कि वे अपनी आय के साधन बढ़ायें ताकि वे अपने विकास कार्यो को फेजड तरीके से कार्यान्वित कर सकें ।

56. Swami Aditya Vesh Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to close B.Ed . classes in the State; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by the Govt. to give employment to B.Ed. Trained Teachersin the State ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) No.

(b) The upgrading of schools is under active consideration of the Government. It would be possible to provide employment opportunities to B.Ed. teachers as and when required for the upgraded schools.

Rate of Seeds

57. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the rate per quintal at which seeds of wheat, gram and barley were purchased by the Government together with the rate per quintal at which the same were sold to the farmers for sowing Rabi Crops during 1977 and whether the rate of seed were less or more as compared to rates in 1976; if more, the reasons therefor ;

(b) the rate at which the fertiliser was purchased and the rate at which the same was sold to the farmers during

the period as referred to in part (a) above ; and

(c) the quantity of fertiliser and seeds demanded separately by the farmers in the State during the period as referred to in part (a) above and the quantity supplied to them during the said period ?

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) रबी, 1977–78 में गेहूं, चना तथा जौ का बीज क्रमशरू 145 रुपये, 222 रुपये तया 100 रुपये प्रति क्विटल की दर से खरीदा गया था तथा रबी 1977 में इन बीजों को क्रमशरू 17 5, 200 तथा 180 रुपये प्रति किवटल की दर से बेचा गया । इस विक्रय मूल्य पर गेहूं पर 52 रुपये चने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान दिया गया । जौ के बीज पर कोई भी अनुदान नही दिया गया ।

रबी, 1976–77 में गेहूं, चना तया जौ का बीज क्रमश 150 रुपये । 202.50 रुपये तया 85 रुपये प्रति क्विटल की दर से खरीदा गया तथा क्रमश 150 रुपये, 135 रुपये और 90 रुपये प्रति क्विटल की दर से बेचा गया । इस विक्रय मूल्य पर गेहूं पर 100 रुपये तथा चने पर 121 रुपये प्रति क्विटल की दर से अनुदान दिया गया । जौ के बीज पर कोई भी अनुदान नही दिया गया था ।

रबी, 1977– 78 में गेहूं के बीज का खरीद मूल्य रबी 1976–77 के खरीद मूल्य से कम था । लेकिन उत्पादकों को यह

अधिक विक्रय दर पर दिया गया । क्योंकि वर्ष 1977– 78 में अनुदान कम दिया गया । चने और जौ का क्रय दर वर्ष 1977–78 में वर्ष 1976–77 की अपेक्षा अधिक था और इनका विक्रय मूल्य भी अधिक था । विक्रय मूल्य का निर्धारण बिक्रीकर, मार्किट फीस, परिवहन खर्च आदि लागतों को सम्मिलित करके तथा बाजार की कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था ।

(बी) जिस दर पर रसायनिक खादें रबी 197 6–7 7 तथा 197 7– 88 के दौरान खरीदे गये तथा किसानों को बेचे गये वे तालिका–। में संलग्न हैं । खादों की कीमतें भारत सरकार हैफेड द्वारा दिनांक 21–5–76, 1– 3– 77, 8– 9–77 तथा 12–10–77 को घटाई गई ।

(सी) (1) खादो की मांग का अनुमान विभाग को फिल्ड एजेंसियों द्वारा खाद की खपत में वृद्धि, सिंचाई के साधनों के विस्तार, फसल योजना में परिवर्तन और अधिक उपजा0 फसलों के अधीन क्षेत्र को ध्यान में दबकर लगाया जाता है । खाद की जो मांग–किसानों द्वारा की गई और जो मांग प्रान्त में स्टाक की गई वह तालिका 2 पर सलंग्न सलंग्न है ।

(2) फसलवार बीजों की विभागीय स्टाफ द्वारा ऐसैस की गई मांग तथा सप्लाई की गई मात्रा निम्नलिखित है : –

(मात्रा क्विटल में)

वर्ष	मांग			सप्लाई की मात्रा		
	गेहूं	चना	जौ	गेहूं	चना	जौ
1976-77	14085	2559	290	27582	8816	403
1977-78	40450	7650	150	58828	14506	95

तालिका – 1

खादों की खरीद तथा किसानों की बिक्री दर रबी 76– 77 तथा 77– 78 (हरियाणा प्रान्त)

क्रंमाक नं.	खाद का नाम	21–5–76 का भाव		1– 3– 77 का भाव		8–9–77 का भाव		12–10–77 का भाव	
		दर खरीद	बिक्री दर किसानों की	दर खरीद	बिक्री दर किसानों की	दर खरीद	बिक्री दर किसानों की	दर खरीद	बिक्री दर किसानों की
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	किसान खाद (25 %)	948	1018	945	1015	945	1015	945	1015
2	किसान खाद (25 %)	985	1060	985	1060	985	1060	985	1060
3	अमोनियम सल्फेट (100	850	925	850	925	1025	1100,	1025	1100

	कि.)								
4	अमोनियम सल्फेट (50 कि.)	860	935	860	935	860	935	860	935
5	यूरिया	1635	1750	1535	1650	1535	1650	1435	1550
6	सुपर फासफेट (50 किलो)	530	605	525	600	525	600	525	600
7	म्यूरियेट आफपटास	820	900	715	795	715	795	715	795
8	डी0 ए 0 पी0	2070	2210	2070	2210	2070	2210	2070	2210
9	एन 0 पी0 के 0 (10:26:26)	2169	2304	1855	1990	1755	1890	1755	1890
10	एन0 पी 0 के 0 (12:32:16)	2429	2564	2085	2220	1955	2090	1955	2090
11	एन 0 पी0 के 0 (14:36:12)	3744	3919	2400	2535	2400	2535	2400	2535

12	एन0 पी 0 के0 (15:15:7½)	1720	1840	1500	1600	1500	1600	1500	1600
13	एन0 पी0 के 0 (15:15:15)	1465	1570	1415	1520	1415	1520	1415	1520
14	एन 0 पी 0 के 0(24:24: 0)	2221	2356	1945	2080	1945	2080	1945	2080
15	जिंक सल्फेट	1850	2000	1900	2000	2100	2200	2100	2200
16	एन0 पी 0 के 0 (8: 8: 8)	--	--	920	1000	1000	1080	1000	1080
17	एन0 पी0 के 0(20:20: 0)	--	--	1835	1950	1835	1950	1835	1950

तालिका– 2

खाद की मांग तथा सप्लाई की मात्रा जो किसानों द्वारा रबी 1976– 77 तथा 1977– 78 में की गई ।

क्रंमाक नं.	खाद का नाम	रबी 1976– 77		रबी 77– 78	
		मात्रा जो मांगी (मि: टन)	बाद की मात्रा जो दी (मि: टन)	मात्रा जो मांगी (मि:टन)	खाद की मात्रा जो दी (मि: टन)
1	नाईट्रोजन खाद	78300	93156	114000	114084
2	फीसफेटिक खाद	13700	17248	24000	28237
3	पोटशिक खाद	5000	6054	12000	8965
	योग :	97000	116458	150000	151286

Milk Plants at Rohtak and Ballabgarh

103. Shri Surrender Singh: Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) the date on which the construction work of Milk Plants at Rohtak and Ballabgarh started ;

(b) whether the plants referred to in part (a) above has been commissioned ; and

(e) if so, the total arrival of Milk in both the said plants separately togetherwith the total expenditure incurred on the setting up of each plant ?

Development Mlnister (Sardar Tara Singh)

(a) The Construction work of Milk Plant at Rohtak started on 20th August, 1973 and at Ballabgarh on 6th March, 1974.

(b) The Milk Plant at Rohtak has been commissioned. The Milk Plant at Ballabgarh has not yet been commissioned.

(c) Milk Plant Rohtak : Handled 7851.15 tonnes of Milk and total expenditure incurred approximately is Rs. 189.92 lac.

Milk Plant Ballabgarh : Question does not arise as the plant is still under construction.

Driking Water Facilities

104. Shri Surrender Singh : Will the Minister for

Irrigation and Power be pleased to state the number of towns given drinking water facilities in the State from 1st April, 1967 to 31st March, 1977 together-with the names and amount spent for the said facility on eacn town separately ?

सिंचाई तथा विजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : 1 अप्रैल, 1967 से 3 1 मार्च, 1977 तक हरियाणा राज्य के 25 शहरों में पीने के पायी की सुविधा प्रदान की गई । इन शहरों का नाम तथा खर्चे का व्यौरा निम्नलिखित है :–

1	जुलाना	8,3488
2	हिसार	7019804
3	पेहवा	223248
4	लाडवा	774239
5	पुंडरी	808177
6	सोहना	532920
7	फरुख नगर	564916
8	पटौदी	419539
9	बावले	671338

10	टोहोना	1893934
11	सिवानी	यह 15 गांवों के समूह में कार्यान्वित की' गई । इसलिए अलग से खर्चा नहीं दिया जा सकता ।
12	कलानौर	695577
13	छछरौली	656718
14	सढौरा	518601
15	नारायणगढ़	655902
16	बुरिया	441087
17	घरोंडा	924005
18	रादौर	657761
	बवानी	
19	खेड़ा	378645
20	हेली मण्डी	222399
21	फतेहाबाद	1299258
22	सफीदों	1222585
23	0चाना	963333

24	कनीना	813900
	अम्बाला	अभी–अभी इसकी मोटिफाईड एरिया कमेटी बनाया गयास है पहले और अब एमःईःएसः अनुरक्षण कार्य किया
25	कैन्ट	जा रहा है
	जोड़	2394471

Villages Connected by Roads

105. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of villages in the State connected by roads on 1-11-67 togetherwith the number of villages connected by roads in Haryana on 31st March, 1977 ?

सिंचाई एंव बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) :

(1) 1386

(2) 5193

Production of Wheat and Rice

106. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total production of wheat and rice in tons in the State during the years 1966-67, 1975-76 and 1976-77 separately?

सिचाई एय बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : हरियाणा राज्य में वर्ष 19 हु क्य 6 7, 197 5– 78 तथा 197 6–

77 में गे हूं एवं चावल का कुल उत्पादन टनों में निम्नलिखित है —

('000' टनों में)

वस्तु	1966— 67	1975— 76	1976— 77
गेहूं	1059	2428	2731
चावल	223	625	317

'A' Class and 'B' Class Officers

121. Rae Dalip Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of offices in the State which are in class 'A' at present ;

(b) the total number of offices which are in class 'B' in the State at present

(c) the criteria of up-grading a class 'B' office to Class 'A' office ; and

(d) the number and the names of the offices which are being considered for up-gradation to class 'A' office ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देरी लाल):

(ए) तेन्तीस

(बी) चौन्तीस

(सी) किसी 'बी' क्लास कार्यालय को 'ए' क्लास में अप–ग्रेड करने के लिए निम्नलिखित मान दण्ड अपनाया जाता है :–

(1) सम्बन्धित कार्यालय में किए जा रहे काम की प्रकृति तथा महत्व।

(2) क्या सम्बन्धित कार्यालय में किया जा रहा काम सचिवालय प्रकृति का है ।

(3) सम्बन्धित कार्यालय में किस सीमा तक कार्य अन्य विभागों के मुख्यालयों में किए जा. रहे कार्य से भिन्न है ।

(4) निहित वित्तीय विवक्षाये ।

(डी) 7. जिन कार्यालयों को 'ए' क्लास में अप–ग्रेड किए जाने के लिए विचारा जा रहा है उनके नाम नीचे दिए जाते हैं ––

(1) निदेशक, पुरातत्व विभाग हरियाणा का कार्यालय ।

(2) निदेशक, अभिलेखागार विभाग हरियाणा का कार्यालय ।

(3) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां विभाग हरियाणा का कार्यालय ।

(4) निदेशक, समाज कल्याण विभाग हरियाणा का कार्यालय ।

(5) निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा का कार्यालय ।

(6) निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा का कार्यालय ।

(7) निदेशक, कृषि विभाग हरियाणा का कार्यालय ।

श्री देवेन्द्र शर्मा (थानेसर) : स्पीकर साहब, मैं प्वायंट आफ इफर्मेशन पर एक बात जानना 'चाहता हूं । अखबारों में बार बार आ रहा है कि निहंगों के चीफ को पांच हजार रुपये नजराना दिया गया लेकिन हमारी सरकार की तरफ से इस बात को रिफयूट किया गया । तो मैं सरकार से आपकी मारफत निवेदन करूंगा कि वह अपनी पोजीशन को यहां क्लीयर करे । क्या यह नजराना है, तोफा है या रिश्वत है?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा वक्तव्य

(1) अध्यानाकर्षण सूचना 1, 2 तथा 5 के सम्बन्ध में ।

Mr. Speaker : The Irrigation and Power Minister promised to make statements on Call Attention Motion Nos. 1,

2, and 5 and 11 today. He may please do so.

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : First, I would make a statement in reply to call Attention Motion Nos. 1, 2 and 5.

यह सत्य है कि पिछले वर्ष की अपेक्षी गन्ना पेलेने के चालू मौसम में गुड़, शक्कर तथा खण्डसारी के मूल्यों में भारी कमी हुई है । परन्तु यह स्थिति सारे देश में है और केवल इस राज्य तक ही सीमित नहीं है यह स्थिति चालू वर्ष में गन्ने का अधिक उत्पादन ' होने के फलस्वरूप पैदा हुई है । हरियाणा राज्य तथा देश में गन्ने के क्षेत्र तथा उत्पादन के आंकड़े पिछले 5 वर्षों के निम्न प्रकार से हैं:—

क्षेत्र हजार हैक्टेयर गन्ने का उत्पादन हजार टन

वर्ष	हरियाणा राज्य		देश	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
1972-73	125	5600	2452	124867
1973-74	149	5930	2752	140805
1974-75	162	5940	2894	144289
1975-76	159	6870	2762	140604
1976-77	168	7280	2872	154023

1977-78	194	8000	3080	165000

(अनुमानित)

(इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुए) राज्य की चीनी मिले गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत पेलने की क्षमता रखती हैं । लगभग 10 प्रतिशत बीज तथा अन्य कार्यो के लिए प्रयोग होता ' है, लगभग 8 प्रतिशत खण्डसारी यूनिटों द्वारा प्रयोग किया जाता है तथा शेष हू लगभग 62 प्रतिशत का आमतौर पर किसानों द्वारा स्वयं गुड़ बनाया जाता है ।

(इस समय मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य अंग्रेजी में आरम्भ किया ।

The sugar mills may not be able to crush more than 18 lakh tonnes of sugarcane even by continuing crushing operations till late in the season out of the total estimated production of 80 lakh tonnes this year. About 5 lakh tonnes may be utilised for seed and the remaining about 57 lakh tonnes will have to be converted into Gur/khandsari sugar. Thus there is a glut of gur and khandsari sugar in the market and the prices of these commodities are ranging at a low level. Recently, the Govt. of India has taken some measures such as 50% reduction in excise duty on khandsari sugar, export of some qty. of gur and purchase of some quantity of gur by the Hafed in some markets of Uttar Pradesh. However, these measures have failed to make any impact on the prices of gur and khandsari and they continue to remain at a low level. Consequently, the farmers are getting a very low return of

about Rs. 7/- per quintal of sugarcane by converting their-crop into gur. I had held a meeting on 17.2.78 with the representatives of the khandsari units and the cane growers. In his meeting it was mutually agreed that the khandsari units will pay the price of cane Rs 8.00 per quintal. Necessary notification fixing the minimum prices of sugarcane payable by the khandsari units @ Rs 8.00 per quintal is being issued by the Govt . This price will be enforced.

The statutory minimum price of sugarcane payable by the sugar mills is fixed by the Govt. of India under clause 3 of the Sugarcane. (Control) Order, 1966. The Govt. of= India had fixed the following prices of sugarcane in respect of different sugar mills in the state for the current crushing season

Statutory Minimum Yamunanagar Karnal Panipat Rohtak Sonepat price fixed by the 9.30 8.50 9.10 9.80 8.50 Govt. of India

(Rs per quintal)

As per provisions of clause 5 A of the Sugarcane (Control) Order, 1966, as from the crushing season 1974-75, besides the statutory minimum price of sugarcane, the sugar mills are required to pay additional price of sugarcane as per second schedule under the said clause 5 A. This additional price is determined by the Cane Commissioner after the close of the crushing season concerned on 30th September. The sugar mills in this state have been paying the price of sugarcane at much higher rate than the statutory minimum

price during the past few years by mutual agreement. In view of this, the additional prices worked out by the cane Commissioner has remained in effective in this state.

It would be seen from the above that legally the sugar mills can he forced to pay only the statutory minimum price fixed by the Govt, of India during the crushing season and additional price determined by the Cane Commissioner, if any, after the close of crushing season. However, they can pay a higher price of sugarcane by mutual agreement.

Like previous years, during the current year also the sugar mills were prevailed upon to pay the agreed price of cane at the rate of Rs. 13.50 per quintal at the factory gate. The sugar mills are required to supply 65 % of their production of sugar in levy quota at the price fixed by the Govt. of India and the remaining 35% they can sell in the free market. They are expected to make good the looses suffered in the levy quota out of the realizations from free sale sugar. The higher price my mutual agreement can also be paid, by the sugar mills out of the realizations from free sale sugar. However,
there has been a fall in the recovery of sugar this year as compared to last year due to various reasons beyond human. control. The figures of recovery obtained during the last year and the. anticipated recovery during the current crushing season in respect of each sugar mills in the tate are given below :—

Recovery %	Yamunanagar	Karnal	Panipat	Rohtak	Sonepat	State

1976-77	9.20	8.20 (trial season)	9.07	9.77	7.37 (trial season)	9.17
1977-78 (anticipated)	8.40	8.20	8.40	9.20	8.00	8.40

In view of steep fall in the prices of gur and khandsari sugar, the prices of free sale sugar have also come down substantially this year and thus the sugar mills are suffering heavy losses by purchasing cane @ Rs. 13.50 per qtl. Whereas, the sugar mills in the cooperative sector are still paying the price of cane Rs. @13.50 per qtl. the Saraswati Sugar Mills, Yamunanagar have reduced the price to the statutory minimum of Rs 9.30 per quintal with effect from 23.2.78. This has caused wide spread resentment in the farmers. However, the plight of the mills is also justified since this year the commulative effect of low recovery of sugar and lower prices of free sale sugar has put the entire sugar industry in a fix,

The Govt. of India is also aware of the problem being faced by the sugar industry and they have recently announced some measures to give some relief to the sugar Industry to tide over the crisis. They have announced the increase in the All India Average Price of levy sugar from the level of Rs. 169/- per quintal to Rs. 187.50 per qtl. wite effect from 1st March, 1978. They will also allow excise rebate to the sugar mills to enable them to continue crushing operations till late in the season beyond 30th April. The details in this

respect will be announced shortly. The Govt. of India have also decided to export 6.5 lakh tonnes of sugar out of 1977-78 quota under International Sugar Agreement. Additional credit facilities will also be provided to Sugar Mills for additional carry over stocks with them as a result of additional sugar production during the current crushing season.

We have requested the Govt. of India to increase the price of levy sugar in respect of the sugar mills in this state from the current level of Rs. 171.73 per qtl. to Rs 240/- per quintal to bail out sugar mills in this state from their present plight. Any price below this level would mean a direct loss to that extent to all the sugar mills in Haryana. Therefore, efforts are being made to get the price of levy sugar fixed at this level so that the Sugar Mills be enabled to pay the price of cane @Rs. 13.50 per quintal.

A meeting of the Sugarcane Control Boards has been held on 1.3.78 to consider the position regarding losses being suffered by the sugar mills and the price of sugarcane payable by them during the current crushing season. It has been decided that whatever the losses to the sugar mills, there should be no reduction in the price of ugarcane being paid by them this year and they will continue paying the price at the factory rate @ Rs. 13.50 per quintal. The cooperative sugar mills will comply with the decision . As regards Saraswati - Sugar Mills, Yamunanagar, the Managing Director, of this mills, Sh.. D, D. Puri is also being pressed that they should pay the price c f cane @Rs. 13.50 per quintal like the cooperative sugar mills as in the past and even if any they have to suffer losses on this account this year they should

bear the same. The state Govt. will make every effort for the payment of this price to the cane growers within the provisions of law.

There is no question of harrasment by the Sugar Mills to the cane growers. The supplied of sugarcane to the mills are regulated under the Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Act, 1953 and the rules framed thereunder. The sugar mills are required to spread the purchase of cane bonded by each grower in an equitable manner throughout the crushing season. In case any specific instances regarding corruption and favourtism in the issue of indents for the supply of sugarcane to the farmers by the authorities of Karnal Coop. Sugar Mills Ltd; Karnal are brought to our notice, these can be looked into and suitable action in accordance with the provisions of law taken against the defaulters.

Comparision of sugarcane to firewood is irrelevant. It takes may years to raise the firewood, whereas sugarcane crop beccmes ready within 8-10 months. Sugarcane contains abcut 70% water and nobody grows it for burning as firewood. In spite of financial difficulties of the mills, efforts are being made to this effect that they continue paying the price of cane @ Rs. 13.50 per quintal and crush maximum quantities of cane even if they have to continue crushing operations till late in the hot season. The Govt. is fully alieve to safeguard the interests of the cane growers in the state.

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : डिप्टी स्पीकर साहब मेरी आपसे दरखास्त है कि गन्ने के रेट्स के विषय में आधे घन्टे की

डिस्कशन मान ली जाये । इस बारे में काफी मैम्बरान बोलना चाहते हैं । हो सकता है कि कुछ मैम्बरान की तरफ से अच्छे सुझाव आ जाये । (विघ्न) –

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, अव टाईम देने की कोई आवश्यकता नहीं है । काफी डिटेल्ड स्टेटमैंट मैंने दे दी है । यदि मेम्बर साहिबान कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत किया जायेगा । वे किसी समय भी लिख कर या मेरे पाम आकर सुझाव दे सकते है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मिनिस्टर साहब को लिख कर सुझाव भेज दे । अब इस पर कोई डिस्कशन नही हो सकती ।

श्री हीरा नन्द आर्य : डिप्टी स्पीकर साहब एक बड़ा गम्भीर मामला है जिम के लिए 11 सदस्यों ने 28 तारीख को कान–अटैनशन मोशन दिया था कि बहालगढ (सोनीपत) के इन्डस्ट्रीयल एरिया मे इन्डस्ट्री के मालिकों ने वरी निर्दयता ने एक मजदूर की हत्या कर दी 30 आर आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई । तो उमके विषय में मैं इन्फर्मेशन चाहता हूं कि हमारी वह काल–अटैनशन मोशन एडमिट हुई है या रिजैक्ट हुई है । (विघ्न

श्री उपाध्यक्ष : उसकी इसलाह स्पीकर साहब की तरफ से आपको चली गई होगी ।

श्री हीरा नन्द आर्य : हमारे पास कोई इतलाह नहीं आई है । विघ्न

श्री उपाधयक्ष : अगर अभी तक आपके पास नही गई हैं तों चली जायेगी । विघ्न

श्री रण सिंह मान : .....

श्री उपाधयक्ष : अब आप बैठिए It should be expunged from the proceedings.

चौधरी भजन लाल :. डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपका केवल एक मिनट लेना चाहता हू । यह बड़ा सीरियस मैटर है । जैसा कि अभी यहां मंत्री महोदय ने कहा है कि यमुनानगर की रिकवरी 8. 40 है और करनाल की 8 20 है करनाल से यमुनानगर की ज्यादा है लेकिन रेटस करनाल के अन्दर ज्यादा हैं । पांच रुपये क्विंटल का अन्तर है । यह बहुत बड़ा अन्तर है । इसलिए आप मेहरबानी करके आधा घन्टे की डिस्कशन अला0 करने की कृ पा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : शाम को बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है उसमें विचार किया जायेगा ।

श्री शमशेर सिंह : थोड़ी देर पहले मैंने लिख कर दिया था कि इस पर आधे घन्टे की डिस्कशन होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : शाम को बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही है । उस टाईम पर विचार हो जायेगा । अब आप बैठिए ।

Shri Verender Singh : I have to make [another statement with regard to Call Attention Motion No. 11.

चौधरी सन्त कंबर : डिप्टी स्पीकर साहब 11 आदमियों ने लिख कर एक काल अटैशन मोशन दी है । सारे सदस्य चाहते है कि उसके बारे में हाउस में जवाब आना चाहिए आज आठ दिन हो चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए । जब वह अला0 हो जायेगी तो जबाब आ जायेगा अब आप बैठिए । (शोर)

चौधरी सन्त कंवर : सदन में जो चीज रखी गई है । उसको आप अला0 कर सकते हैं दूसरे यदि सदन चाहता है तो आपको अला0 कर देनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए (विघन)

श्री मूल चन्द जैन : आन ए प्वांएट आर्डर सर । अभी मंत्री महोदय ने जो स्टेटमैंट पढ़ा है । इसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई फेवरेटिज्म या क्रप्शन करनाल शूगर मिल में हुई हो तो सरकार के नोटिस में लायी जाये । तो मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हू । डिप्टी स्पीकर साहब, 18 तारीख को काल अटैन्शन मोशन दी गई और आज 6 मार्च है । इस काल– अटैनशन मैं

खासतौर पर लिखा था कि जो. शूगर–केन बाउन्डिड है, उसका बाज का तो छ परसैन्ट गन्ना ले लिया और बाज का अभी 20 परसैन्ट भीनहीं लिया है । क्या मिनिस्टर साहब देख नहीं सकते है कि फर्क क्यों हो रहा है । उनके अकाउन्टस से पता लग सकता है कि किस योअर का गन्ना 80 परसैन्ट आया है और किस का 20 परसैन्ट आया है । वार स्वयं पता लगायें कि वहां पर यह मिचुऐशन है या नहीं, वहां पर यह भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ ।

Mr. Deputy Speaker : I would draw the attention of the hon. Member to Rule 73. Sub-rule(2) of this Rule says that there shall be no debate on such statement at the time it is made. So, I disallow it.

श्री मूल चन्द जैन : मैं डिबेट नहीं मांग रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं–– कि जो स्टेटमैंट इन्होंने दिया है यह अधूरा है । इनको पूरा स्टेटमैंट देना चाहिए था । काल अटैन्शन मोशन में मिनिस्टर साहब की तवज्जोह खास तौर पर इस. बात को ओर दिलायी गयी थी कि को हैरास किया जा रहा है, इसलिए मेरा कहना यह है कि स्टेटमैंट पूरा नही दिया गया है इन्हे पूरा स्टेटमैंट देना चाहिए था ।

श्री उपाध्यक्ष जैन : साहब! आप बैठ जाइये, जवाब तो आ चुका है ।. (विध्न)

चौधरी सन्त कंवर : डिप्टी स्पीकर साहब यह बड़ा जरूरी मसला है, इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन हो सकती है । आप हाफ एन आवर डिस्कशन अला0 कर दीजिए ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : कोई प्रोवीजन नहीं है ।. (विध्न)

चौधरी सन्त कंवर : प्रोवीजन है ।. (विध्न)

Mr. Deputy Speaker : We should go according to the provisions of the Rules.

चौधरी सन्त कंवर : चौधरी साहब, मैं यह मानता हूं कि आप बहुत अच्छे वकील हैं । लेकिन प्रोवीजन बनाने वाला कौन है, प्रोवीजन बनाने वाला यह सदन ही तो है ।

(2) ध्यनाकर्षण सूचना सं. 11 के सम्बन्ध मे

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): 1 would now make a statement on Call Attention Motion No. 11 given notice of by Sarvshri Bhajan Lal, Shanker Lal, Mool Chand Jain and Sukhdev Singh M.L.As.

इस वर्ष हरियाणा में लगभग 2.‟ ला? हैक्टेयर क्षेत्र में कपास उभाई गई थी । हुस फसल के अधीन लेव मौसम, गत वर्ष के मूल्य तथा ग्रीष्मकालीन वर्षा के कारण 1. 83 से 2 र 70 लाख हैक्टेयर की सीमा तक घटता व बढ़ता रहा है । राज्य में कुल कपास का उत्पादन मुख्य रूप से मध्यम रेज वाली कपास की किस्मों 320 एफ एच 14 व जे 34 (बिकानेरी नर्मा) का 55

प्रतिशत तक ु तथा शेष लगभग 45 प्रतिशत छोटे रेशे (देसी) कपास के रूप में होता है । मव्यम रेले वाली कपास जिमका पिरू देश में अभाव है 640 रुपये प्रति क्विंटल की उच्च दर से आयात की जाती है । राज्य में मध्यम तथा छोटे रेशे वाली कपास का कुल उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 7 से 8 प्रतिशत भाग ही होता है । परन्तु यह फसल राज्य के एक तिहाई कृषिकों को आर्थिकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । हरियाणा राज्य ने गत वर्ष कपास का उत्पादन अधिकतम था । जब कि इसका उत्पादन 476 हजार गांठों तक पहुंच गया था ।

कपास का विपणन

राज्य में कपास का विपणन 'नियमित मण्डियो में खुली बोली के द्वारा होता है । इस खुली प्रतियोगिता में व्यापारियो के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं जैसे कि सी0सी0आई0, हैफड तथा खादी ग्रामोद्योग द्वारा भी कपास खरीदी जाती है । परन्तु भारतीय कपास निगम सबसे बड़ी सरकारी खरीद करने तथा बेचने वाली एजेन्सी है जो कि हरियाणा में 197 0– 71 से क्रियाशील है । भारतीय कपास निगम का कपास मण्डियों में एक प्रभावशाली खरीददार के तौर पर इमका मुख्य उद्देश्य कपास की कीमतों ने स्थिरता स्थापित करना है । गत् वर्षो में हरियाणा में भारतीय कपास निगम द्वारा की गई खरीद निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	खरीद	खरीदी गई	उत्पादन में प्राप्ति की

	केन्द्रों की संख्या	मात्रा गांठों में	प्रतिशतता	
1971-72	6	20,932	4.8	प्रतिशत
1972-73	13	88,000	21.0	प्रतिशत
1973-74	14	30,000	6.9	प्रतिशत
1974-75	2	500	0.12	प्रतिशत
1975-76	7	6,835	1.5	प्रतिशत
1976-77	6	38,993	8.2	प्रतिशत
1977-78	9	45,000	9	प्रतिशत

भारतीय कपास निगम ने वर्ष 1971– 72, 1972–73, 1973–74 तथा 1976–77 में मूल्यो में स्थिरता स्थापित कर रुषको की सहायता की है ।

वर्ष 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान कुछ वित्तीय कठिनाईयों के करिय यह संस्था कपास की कोई महत्वपूर्ण मात्रा न खरीद सकी इसके अतिरिक्त वर्ष 197 5– 76 से भारतीय कपास

निगम मुख्य रूप से भारतीय वस्त्र निगम के अधीन आने वाली रोगी मिलों के लिये कपास खरीद रही है । मूल्यो में स्थिरता स्थापित करने की दृष्टि से भारतीय कपास निगम की उपयोगिता तब से कुछ सीमित हो गई है ।

कपास का समर्थन मूल्य

भारतीय सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार कपास का समर्थित मूल्य निर्धारित करके इसके उत्पादकों के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करती है । राज्य सरकार द्वारा वर्ष प्रति वर्ष उत्पादन लागत के आधार पर कृषि मूल्य आयोग को सुझाव देती है ताकि उनकी सिफारिशों के अनु मार भारत सरकार कपास उचित समर्थित मूल्य निर्धारण कर सकें । परन्तु भारत सरकार द्वारा गत वर्षों में निर्धारण किया गया समर्थित मूल्य कम था । इसमें मण्डियों में मूल्यों पर इसका प्रभाव नगण्य रहा । चालू मौसम में भारत सरकार ने कपास की किस्म 320–एफ तथा एच–14 का क्रमश 225 रुपये प्रति क्विटल तथा 252 रुपये प्रति क्विटल समर्थित मूल्य निर्धारित किया गया । गत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा मांगा गया समर्थित मूल्य तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का विवरण निम्न प्रकार से है :–

विभिन्न वर्षों में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मांगा गया मूल्य तथा भारत सरकार द्वारा निधारित मूल्य रुपये /क्विटल :–

	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78
राज्य सरकार द्वारा बांच्छित	250	350	300	350
1 अमेरिकन	215	--	-	--
2. देसी				
भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य	195	210	--	255
1. 320–एफ	195	216	--	262
2. एच– 14		170	-	210
3 देसी	250	350	300	350

भारत सरकार द्वारा निर्धारित इस वर्ष के लिये समर्थित मूल्य राज्य सरकार के विचार में बहुत कम होने के फलस्वरूप भारत सरकार को मध्यम रेशे वाली कपास का समर्थित मूल्य 175/– रुपये क्विटल तक बढ़ाने के लिये सिफारिश की गई थी । इस सुझाव का आधार यह था कि वर्ष 197 6–7 7 में मण्डी में कपास का मूल्य लगभग 475 रुपये प्रति क्विटल रहा था । राज्य सरकार कपास के चालू मौसम के आरम्भ (197 7–7 8) से ही इस विषय में रुचि ले रही है 'कि कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य अवश्य मिले । भारत सरकार को भारतीय कपास

निगम को निवेश देने की प्रार्थना की गई थी कि वह राज्य कोई 1 6 महत्वपूर्ण कपास मण्डियों में प्रभावशाली ढंग से खरीद करे ओर दो लाख गांठों तक कपास की खरीद की जाये ताकि गत वर्ष का मूल्य स्तर बनाया रखा जा सके ।

चालू मौसम के दौरान कपास की कीमतें

चालू कपास के मौसम में कपास की कीमतें दिसम्बर, 1977 से जनवरी, 1978 के दौरान गत मौसम की तुलना में अधिक रही है चूंकि इस सीजन में भारतीय कपास निगम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल ने भी देसी कपास की खरीद आरम्भ कर दी थी । देसी कपास का अनुमानित उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम है । देसी कपास की कीमतें उपरोक्त समय के दौरान 344 रुपये से 387 रुपये प्रति क्विटल के बीच रहीं जो कि गत वर्ष कैं इसी अवधि की अपेक्षा से 44 रुपये से 74 रुपये प्रति क्विटल तक 0ंची रही । परन्तु जनवरी के अन्त में मूल्यों में भारी गिरावट देखी गई जबकि इसका मूल्य गिर कर 304 रुपये प्रति क्विटल तक आ गया जो कि गत वर्ष की तुलना में 63 रुपये प्रति कि 0 कम था ।

अमेरिकन कपास

मध्यम रेशे वाली कपास (अमेरिकन) का मूल्य अक्तूबर, 1977 के दौरान आरम्भ में निम्न स्तर पर रहा तथा गत वर्ष के मूल्यों की तुलना मे लगभग 35 रुपये प्रति कि 0 कम रही । इससे राज्य सरकार व उत्पादकों में भारी चिन्ता हुई । अतः हरियाणा

सरकार ने भारत सरकार तथा कपास निगम का ध्यान इस ओर आकर्षित किया । मुख्य मन्त्री महोदय ने भी भारत सरकार के साथ कई बार इस बारे में विचार विमर्श किया तथा भारतीय कपास निगम के साथ भी कई बार विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क स्थापित किया गया, ताकि राज्य में कपास की खरीद आरम्भ करवाई जा सके तथा खरीद केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाये । भारतीय कपास निगम के प्रतिनिधियों द्वाराइस सम्बन्ध में बताई गई समस्याओं का भी तुरन्त समाधान किया गया इन प्रयत्नो के फलस्वरूप भारतीय कपास निगम ने गत मौसम के 6 केन्द्रों की तुलना मै इस मौसम में 9 मण्डियों में कपास की खरीद की है । चालू सीजन में गत वर्ष की खरीदी गई 39000 गांठों की तुलना में 45000 गाठें खरीदी जा चुकी है । समय समय पर पतों व व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि चूंकि आयात की गई कपास मूल्य 640 रुपये प्रति किव 0 तक चुकाया जाता है । अतएव यदि वह हरियाणा के उत्पादकों को हीं अच्छा मूल्य प्रदान करे तो हमारे कृषक अधिक कपास उगायेंगे जिससे विदेशों से कपास आयात करने की आवश्यकता नही रहेगी । मध्यम रेशे वाली कपास का मूलय नवम्बर के मास में काफी अच्छा हो गया और गत वर्ष के लगभग बराबर या माम्त्री कम अर्थात 7 से 1 5 रुपये प्रति क्विं 0 तक आ गया । फरवरी, 1978 तक यह मूल्य गत वर्ष के मूल्य के स्तर के बराबर रहा परन्तु गत वर्ष की तुलना में फरवरी माम में अमेरिकन कपास की कीमतों में 100 रुपये से 110 रुपये प्रति क्विं0 तक की– भारी गिरावट देखने

में आई । फरवरी मास में मूल्यों में आने वाली गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(1) बिजली के अभाव के कारण मिलो में बिना जिनिंग का स्टाक बहुत बढ़ गया जिससे फैक्टरियों की पूंजी और बहुत सा स्थान रुक गया इससे निजी फैक्टरियों तथा भारतीय कपास निगम को अपनी खरीद बन्द कर देनी पड़ी । बिजली की कमी दूर करने की ओर सरकार ने पूरा पूरा ध्यान दिया जिससे अब कपास के स्टाकों की जिनिंग एवं प्रेसिंग शीघ्रता पूर्वक की जा रहा है । शीघ्र ही स्थिति में सुधार आने की आशा है ।

(2) अन्य राज्यों जैसे कि गुजरात कथा महराष्ट्र में भी कपास का नया मौसम आ जाने व वहां पर फसल अनुमान इस वर्ष काफी अच्छा होने के कारण अधिकतर खरीद उन क्षेत्रों में आरम्भ हो गई ।

(3) हरियाणा में अच्छी कीमतों के फलस्वरूप जनवरी मास के दौरान पंजाब से काफी कपास हरियाणा की मण्डियों में बिकने के लिये आनी आरम्भ हो गयी ।

1977– 78 में कपास की विभिन्न किस्मों की मासिक तुलनात्मक तालिका निम्न प्रकार से है :–

मास	1977– 78

	देसी	अमेरिकन
अक्तूबर	*	376
नवम्बर	344	403
दिसम्बर	387	445
जनवरी	365	428
फरवरी	304	466

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा कपास मण्डी में आई रुकावटों को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को आग्रह किया है कि भारतीय कपास निगम को हरियाणा में खरीद के कार्य को और तीव करने का निर्देश दिया जाये । परन्तु फिर भी भारतीय कपास निगम को राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन रोगी मिलों–कें लिये कपास खरीदने की वर्तमान नीति के कारण उसकी अपनी भी कुछ सीमाएं है । यद्यपि सीः सीः आईः का राज्य की मण्डियों में प्रवेश कपास की कीमतों में सुधार लाने मे काफी सहायक सिद्ध हुआ है ।

भारतीय कपास निगम भी इस स्यिति का जायेजा ले रही है तथा इस दिशा में आवश्यक पग उठा रही है । आशा की जाती है कि स्थिति में शीघ्र ही सुधार होगा । राज्य सरकार भी इस ओर से पूर्णतया स्तर्क है, ताकि उत्पादकों को उनकी कपास

का उचित मूल्य दिलवाया जा सके । इसके लिये सरकार की ओर से हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

चौधरी भजन लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले साल कपास का भाव पांच सौ रुपए क्विंटल थाऔर इस साल 350 रुपए प्रति क्विटल का भाव चल रहा है । मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार को बीच में आना चाहिए जिससे कि किसान को ठीक कीमत मिल सके । डिप्टी स्पीकर साहब, 400 रुपए प्रति क्विटल कम से कम कपास किसान के घर आकर पड़ती है । जब तक सरकार बीच में नही आएगी तब तक किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : डिप्टी स्पीकर साहब, इस पर डिस्कशन होना मान ले कोई सुझाव देकर हम इनके हाथ मजबूत करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए अलग से नोटिस दे दीजिए विचार हो जाएगा ।

कामरेड शंकर लाल : आन ए प्वायट आफ आर्डर । मेरा एक काल अटेन्शन मोशन नम्बर 16 था वह एडमिट हुआ या नही । उसकी बाबत मेरे पास कोई जवाब नही आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह एग्जामिन होगा । उभकी इन्फरमेशन आपके पास आ जाएगी ।

वर्ष 1977–78 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त)

(1) राज्य के राजस्वों पर प्रभारितव्यय के अनुमानों पर चर्चा

Mr. Deputy Speaker : Now the House will discuss the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1977-78. Those hon. Members who wish to discuss the charged items may please do so.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : डिप्टी स्पीकर महोदय मैं चार्ज्ड आइटम्ज पर बोलना चाहता हू । यह जो सप्लीमेंटरी डिमान्डज हाउस के अन्दर पेश को गई हैं वे 14 करोड़ रुपए के करीब हैं और उनमें पन्द्रह–सोलह लाख की चार्ज्ड आइटम्ज है । वैसे तो चार्ज्ड आइटम पर हाउस के अन्दर राय नही ली जा सकती । यह पन्द्रह–सोलह लाखकी चार्ज्ड आइटम कैसे हो गई इसके बारे में मैं थोड़ा सा मरकर का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो पन्द्रह सोलह लाख की रकम है वह मुखतलिफ कामों के लिए जैसे कही मंडियां बनाने, कहीं जमीन एक्वायर करने और उसकी कीमत. लैड एकजीवीशन आफिसर द्वारा कम देने पर होई कोर्ट अथवा किसी दूसरी कोर्ट कें द्वारा ज्यादा दिलवाने आदि पर खर्च की गई हैं इस पन्द्रह सोलह लाख की रकम में से 12–13 लाख रुपया लैण्ड एकवायर करने के बाद ज्यादा कम्पेनशेसन देने के लिए है । मैं सरकार को कहना चाहता

हूं कि वह लैंड एक्वीजीशन आफिसर्ज को यह आदेश जारी करे कि जब भी किसी जमीदार अथवा किसी और आदमी की जमीन एक्वायर करें तो कि ठीक क्या से न्यायपूर्ण तरीके से जमीन का मुआवजा लगाकर पैसा दो अगर जमीन का ठीक पैसा नहीं दिया जाता तो आठ–आठ, दस–दस साल किसान को परेशानी उठानी पडती है और फिर की बढी कीमत मिलती है जिससे कितना का काम चलता है। सरकार यह हिदायत जारी करे कि लैड़ एकवीजीशन आफिसर जिस काम जमीन एकवायर करे और एक्वायर करने के टाईम जो जमीन का मार्किट रेट हो वह कीमत लैंड ओनर को दी जाए । यह जो पैसा दिया जा रहा है इसमें हमारी सरकार का कसूर नही है क्योकि यह पांच छ वर्ष पुराना है । हमारी सरकार का कोई कसूर नही है लेकिन हमारी सरकर को यह हिदायत अब जारी कर देनी चाहिए कि लेकिन एक्वायर करते समय मार्किट रेट पर पैसा दिया जाए ।

दूसरा मेरा प्वायट यह है जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई है वह है हमारे गवर्नर श्री चक्रवर्ती साहब के दाह संस्कार पर इतना पैसा खर्च किया गया । डिप्टी स्पीकर साहब, चक्रवर्ती साहब के दाह संस्कार पर 79350 रुपए यानी लगभग 80, हजार रुपए खर्च किए गए है । जिन लोगों ने यह 80 हजार रुपया खर्च किया हो सकता है कि वे दस–बीस लाख रुपया भी खर्च कर दे ते । मुझे सब से बडी तकलीफ यह कि अस्सी हजार रुपया कैसे खर्च कर दिया । यह हमारी सरकार ने नही किया

बल्कि जो पिछली सरकार थी जो पिछली कैबिनेट थी उसक भुगतान किया जा रहा है । यह भी सोचने की बात है दिय इस किस्म का खर्चा चार्ज्ड आइटम में कैसे हो क्या । गवर्नर की तनखाह या गवर्नर के ए0 डी0 सी0 की तनखाह तो चार्ज्ड आइटम में आ सकती है लेकिन गवर्नर के दाहसंस्कार का खर्चा चार्ज्ड आइटम में कैसे हो गया । यह एक बड़ी अजीब बात है । मैं सरकार को कहना चाहता हू कि यह अस्सी हजार रुपए का खर्चा उन लोगों से, उस कैबिनेट के लोगों से वसूल किया जाना चाहिए जिन्होंने यह खर्च करवाया था । डिप्टी स्पीकर साहब, इस अस्सी हजार की बजाय उसके दाह संस्कार पर आठ लाख रुपया रग बीस लाख रुपया खर्च कर देते जैसे अर्थी जब जा रही– हो तो सोने कें चांद और सिक्के बिखरने चले जाते, तब क्या यह खर्चा ठीक रहता । क्या मरकर ऐसा नहीं कर सकती कि यह रुपया उस वजारत से वसूल किया जाए जिन्होने यह खर्च किया है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तीसरी बात लैन्ड एक्वीजीशन के मरे ये कहना चाहता हू, ऐसे केसिज में सरकारी वकील सरकार की तरफ से पैरवी करते है । जब किसी आदमी को जमीन का मुआवजा न मिले तो वह केस डिस्ट्रिक्ट सैशन जज यह ले जाना है डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज मूआवजे की रकम निर्धारित करता है क्यके बाद मामला हाई कोर्ट मे जाता है जिसके ये सरकार की तरफ से जो वकील पेश होते हैं उनको भारी रकम दी जाती है

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी एक वकील हूं, आप भी वकील हैं, इस माग के द्वारा भारी रकम सरकारी वकीलों कोदो गंदी है जोकि उचित नहीं है । दो केसिज मैं ही 17260 रुपये के लगभग सरकारी वकीलों को फीस के तौर पर दिया गया हैं ओं मुझे समझ नहीं आता कि हमने एडवोकेट जनरल के दफ्तर में इतनी लम्बी चौड़ी लाईन काहे कौ लगा रखी है, काफी स्टाफ है, डिप्टी एडवोकेट जनरल है, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल है । एंसिसटैन्ट एडवोकेट जनरल हैं आखिर यह सब लोग किस काम के लिये वहां पर बैठा रखे हैं डेनको इनके काम के लिये तनख्वाहें मिलती हैं ताकि ये लोग सरकार के केसिज 'के बारे पैरवी करे । ''इसलिये इन्हें अलग पैसा क्यों दिया जाता है, इनको अपनी उसी तनख्वाह के पर ही सरकार के केसिज की पैरवी करनी चाहिये, आखिर यह जो पैसा है यह सरकारी कन्सोलीडेटिड फण्डज है, जनता का पं सा है! इसको इस तरह से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिये ओं इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार इस प्वांयट को फिर एग्जामिन करे । मैं यह सरकार 'के नोटिस में लाने के लिये यहां पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, आप माइंड न करें, यह जो बात मैं कहने जा रहा हूं आप से भी सम्बन्धित है । डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह अप्रैल, 1977 में 800 से 1500 रुपये हो गई (चीफ पार्लियामैट्री सैक्रेटरी की तरफ से विल) चीफ पार्लियामैंट्री

सैक्रेटरी साहब, यहां पर सरकारी फण्डज का सवाल है । पब्लिक फण्डज का सवाल है, यह कोई हमारी या आपकी जायदाद का सवाल नहीं है । इस बारे में डिप्टी स्पीकर साहब, हमने परसों भी बहस की थी, आखिर । पे स्केलज का कोई स्टैडर्न्ड होना चाहिये । यह नही होना चाहिये कि एक मिनिस्टर भी 1500 रुपये ले और एक डिप्टी स्पीकर मिनिस्टर भी 1500 रुपये ले, स्पीकर भी 1500 रुपये ले और डिप्टी स्पीकर भी । यह बात मेरी तो समझ में नहीं आती, इस लिये सरकार के सामने मेरा एक सुझाव है कि इस तरफ भी कोई ध्यान दिया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक और आइटम पर अपनी बात कहकर मैं बैठूगा कि एक सिपाही ने अपनी राइफल में गोली भरी और वह किसी दूसरे सिपाही को लग गयी । वह सिपाही जख्मी हो गया! जख्मी होने से वह बेकार हो गया । बेकार होने के बाद उस बे चारे को नौ करी से निकाल दिया गया । जो सिपाही हटाया गया उसने उस सिपाही पर और सरकार पर मुकदमा दायर कर दिया और उस सिपाही को मुकदमा जीतने पर कोई लगभग 38 हजार रुपये की अदायगी की जाएगी । सरकार ने डिमांडज में इस बारे में कलीयर कुछ नहीं बताया । मैं फायनैंस डिपार्टमैंट और अपनी सरकार से कहूंगा कि सप्लीमैंट्री डिमांडज के बहाने यह खर्चा कैसे हुआ, क्यों हुआ? इस मामले में सरकार ने अपनी किताबों में कुछ नहीं बताया जबकि इनको बताना चाहिये । जब बजट पेश होता है तो चपरासी से लेकर पर तक बताया जाता है

कि बजट मे इन इन आईटमज पर इतना इतना खर्चा होगा । बड़ी हैरानगी कीं बात है कि हमें उन खर्चों के बारे में कुछ पता ही न लगे । जब वोटिंग होगी तब मैं इस बारे में और कुछ बता0ंगा । इन डिमांडज के. द्वारा ' करोडो रुपये की मन्जूरी चाहेंगे, मैं बता0ंगा कि डिप्टी स्पीकर साहब, सिपाही की वजह से 38 हजार रुपये का खर्चा इस सरकार के खुजाने पर पड़ा है पर–जिस सिपाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ । उसके बारे कुछ नहीं बताया गया कि सरकार ने उस के खिलाफ क्या कार्यवाही की है । एक्सीडैंट तो एक सिपाही की वजह से हुआ हो और खर्चा पडे सरकार के पर, पब्लिक के पर, यहं हसारी समझ में नहीं आया एक सिपाही ने गल्ली की उसके बारे में हमारी सरकार ने क्या किया, मैं इस बारें में अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह इस बारे में बताएं किं ऐसा क्यों, कैसे हुआ और उस सिपाही के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? इन सारी बातों का यहां पर जिकर आना चाहिए था । इन बातों के साथ मैं अश्वका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । डिप्टी स्पीकर साहब, इस वक्त मैं बस इन डिमांडज पर ही बोलना चाहता था, शेष बजट पर बोलते हुये अपने ख्यालातों का इजहार करूंगा ।

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Deputy Speaker : According to the previous practice and in order to save the time of the House all the following Demands for Grants appearing on the order paper

will be deemed to have been read and moved together.

The hon. Members can raise discussion on the Demands but while speaking they will have to indicate the demand No. on which they want to raise discussion. हाउस पांच बजे तक चलेगा, उस के हिसाब से आप टाइम ले लीजिए।

That a supplementary sum not exceeding Rs. 62,45,345 be granted' to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 95,63,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 4--Revenue.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,19,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment

for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,01,98,480 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 8—Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,95,60,095 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending

31st March, 1978 in respect of Demand No. 9 —Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 16 —Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 47,10,660 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of ipayment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 17 —Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 71,59,940 be granted to the Governor to defray the charges fiat come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 20 —Forest .

That a supplementary mum not exceeding Rs. 92,31,841 be granted to the Governor to defray the Charges that will come in the course of payment tor., the year ending 31st March, '1978 in respect, of Demand No. 21 Community y Development

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No 25—Loansand Advanecs by the State Government.

स्वामी आदित्यवेश (हथीन) : उपाध्यक्ष महोदय. यह जो अनुपूरक अनुमानों पर हमारे सामने हाउस मे बहस चल रही हैं मैं उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हू । इसमें बहुत सी ऐसी

बाते हए जिनको पढकर उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा आश्चर्य होता है । खर्चा पहले कर लिया जाता है और उसको बाद में हाउस से पास करवाया जाता है । पैसा खर्च कर लेने से पहले सदन में सदस्यों के सामने सा री मांगों को रखा जाना चाहिये । मैं सारी बातें एक एक करके आपके सामने रखगा । अभी जैन साहब ने कहा कि एक गवर्नर साहब के दाह संस्कार पर बड़ी भारी रकम चर्च कर दीगई जबकि हमारा देश इतना गरीब है, वहां की जनता बहुत दुखी है, दाने दाने के लिये मोहताज है । मैं यह चाहता हूं कि यह सारे का सारा पैसा भूतपूर्व सरकार से वसूल किया जाये उस पैसे का हिसाब इस सरकार के जिम्मे नहीं आना चाहिये । इसी प्रकार पुलिस पर भी काफी पैसा खर्च किया जा रहा है कोई लगभग 6 2, 4 5, 345 रुपये का खर्चा किया गया है । प्रोमोशनज के पर, उनकी नई नियुक्तियों के पर इतना पैसा खर्च किया गया है, मैं समझता हूं कि यह उचित नही है । पुलिस करती क्या है, इम बारे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पलवल के सब डिवीजन के घमाखा गाव में 3 फरवरी को किसी को 'गन्ने के खेत में मार दिया गया मोर बाद मे लोगों ने उस अपराधी को पकड़वा भी दिया लेकिन जौ अपराधी था, उसे याद में छोड़ दिया गया । इसी तरह से पलवल के हल्का मे एक गांव में दो डाकू जेलमें बन्द थे, वे भाग गये – (विघन) –

चौधरी संत कंवर : डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी जी से यह तो पूछ लिया जाए कि वे किस मामले पर बोल रहे हं?

श्री उपाध्यक्ष : स्वामी जी, बोलने से पहले आप अपनी डिमांड नम्बर बता दीजिये कि आप किस डिमांड पर रोल रहे है ।

स्वामी आदित्यवेश : मैं डिमांड नम्बर 3 पर बोल रहा हूं, जिम में पुलिस विभाग के लिये 62,45,345 रुपया रखा गया है, अस. सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि पुलिस के लिये इतना अधिक पैसा रखा गयाहै और जिस की मांग की गई है यह भी देखे कि आखिर पुलिस विभाग कोई काम भी करता है, उसकी कार्य कुशलता क्या है ?

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब मैं बताना चाहता हूं कि सरकार के खिलाफ 54 मुकदमे थे जो सरकार सारे के सारे हार गई और सरकार को 73, 587 रुपये वकीलों को फोम के तौर पर दंने पड़े और फिर हारने के बाद जिन से सरकार पराजित हुई उन्हें कोई लगभग 225389 के लगभग रुपये देने पड़े । इसलिये मैं चाहूंगा कि जो मुकदमों की प्रकृति हैं इसको समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर आम जनता दई देखती है कि सरकार मुकदमो की तरफ जा रहीहै तौ जनता भी उसका अनुसरण करेगी । इसलिये यह प्रवृति समाप्त होनी चाहिये ।

इसी तरह से मांग नम्बर 4 पर मैं बोलूंगा । इस खर्च के लिये मैं सरकार का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । क्योंकि यह हरियाणा के इतिहास में पहली मिसाल है । वैसे हरियाणा पिछने 10– 1 1 साल से तबाह होता रहा है लेकिन बाढ़ पीड़ितों

की सुरक्षा के लिये इतनी बड़ी राशि आज तक कभी भी खर्च नहीकी गई थी इसलिये मैं –सरकार को धन्यवाद देता हूं । इसी प्रकार से मांग नम्बर 8 के बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं । इस डिमांड के जरिये सरकार ने सड्कों और पुलो पर लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला लिया है । मैं चाहूंगा कि यह सारा पैसा सिरसा, हिसार और भिवानी में ही खर्च नही होना चाहिये बल्कि यह सारे हरियाणा में खर्च होना चाहिये । अभी पिछले दिनों मे एक सवाल के उत्तर में बताया गया था कि जब से जनता सरकार बनी तब से कुल साढ़े सैतीस किलोमीटर सड़कें बनी और इसमें से साढ़े छत्तीस किलोमीटर सिरसा, हिसार और भिवानी में बनी है । तो इस प्रकार से यह जो 6 करोड़ रुपये हैं यह सिर्फ सिरसा, हिसार और भिवानी पर ही न खर्च किया जाए बल्कि इसे सारे हरियाणा में खर्च किया जाए ।

इसी प्रकार से मैं मांग नम्बर 9 पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं । सरकार ने जो मंहगाई भत्ते की अदायगी के लिये पैसा मांगा है इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं क्योंकि अध्यापकों के मंहगाई भत्ते में जो कटौती होती थी उसको बन्द करने की वजह से यह खर्चा हुआ यह बड़ा अच्छा फैसला है । इसी माग से सबंधित धरौंडा में जो पाठशाला के लिये राशि मांगी गई है उसका भी समर्थन करता हूं । लेकिन जो भोजन 40 हजार विद्यार्थियो को दिया जाएगा यह निशुल्क होगा या शशुल्क इसके बारे में कोई उल्लेख नही किया गया है । इसके अलावा मै यह

समझता हू कि हमारे हरियाणा में गरीब बच्चों की तादाद जो कि पढ़ रहे है 40 हजार से बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल में यह संख्या 5– 7 लाख होगी इसलिये यह खर्च और भी ज्यादा होना चाहिये ताकि हरियाणा के सभी गरीब बच्चों को इससे फायदा हो सके । इसी प्रकार से इसी मांग से संबंधित जो प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का प्रोग्राम है इसके लिये सरकार ने जो राशि मांगे हैं मैं उसका समर्थन करता हूं । इसके तहत सरकार ने प्रान्त के गरीब बच्चों को पाठ्य सामग्री देने का प्रोविजन रखा है । यह काम जितनी जल्दी अमल में लाया जाए उतना ही अच्छा है । इसी मांग के अन्तर्गत जो 27 लाख रुपये महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय को अनुदान देने के लिये मांगा गया है यहभी बहुत अच्छा कदम है मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों को अधिक–से अधिक अनुंधान ' दिया जाए ताकि ये और आधिक विकसित हो सकें । महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालयको अगर और भी विकसित कियाजाता है तो वास्तव में यह हरियाणा के लिये गौरव की बात होगी।

इसके बाद मैं मांग नं. 16 पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा । इसमें सरकार ने 25 लाख रुपये लघु उद्योगों के लिये मांगा है । इसके अन्तर्गत छोटे छोटे उद्योगपतियो को 20 हजार रुपये तक का ऋण देने की व्यवस्था 'की गई है लेकिन इसमें 50 हजार की आबादी की शर्त लेगा दी है । मैं चाहूंगा कि अगर 50 हजार से कम वाली आबादी के लोगों को भी यह ऋण दिये जाएं तो उसमें गांव भी आ जायेंगे, नोटिफाइड एरिया भी आ जाएगा और कमेटी

का एरिया भी आ जाएगा । 50 हजार की आबादी में तो बड़े ? बड़े शहर ही आएंगे और छोटे छोटे गांव रह जाएंगे इसलिये सरकार अगर छोटे गांव की तरफ भी ध्यान देगी तो इससे हमारा विकास और भी ज्यादा होगा ।

इसके बाद मैं मांग नं. 1 7 के बारे में थोड़ी सी बाते रखना चाहता हूं । इसमें सरकार ने कुछ जननि अक्वायर की और जमीन के मालिक को पूरा पैसा नही दिया जिस कारण उसने मुकदमा दायर कर 'दिया और सरकार हार गई और सरकार को इस कारण 81 605 रुपये देने पड़े । इसी तरह से नारायणगढ, रिवाडी तथा गुड़गांव की मंडियों का मामला है । मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सरकार को मुकदमों में पड़ने की बजाए आपस में समझौता कर लेना चाहिये । समझौता कर लेने से ज्यादा अच्छा रास्ता निकल सकता हैं ।

इसी तरह मांग नं. 20 पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं । सरकार भारत को हरा–भरा बनाने के लिये इस स्कीम पर 35 लाख रुपया खर्च करना चाहती है । इस पैसे से सरकार जंगल पैदा करना चाहती है लेकिन मुझे तो कही पर अच्छा जंगल दिखाई नही देता है और केवल कीकर ही दिखाई दे रही हैं । अगर सरकार अच्छे वृक्षों को लगाने की तरफ ध्यान दे जैसे फलदार वृक्ष हैं या जैसे लकड़ी देने योग्य वृक्ष हैं तो यह स्कीम ज्यादा सफल रहेगी ।

इसके बाद मैं मांग नं. 21 पर बोलना चाहता हूं । इसमें समेकित ग्रामीण प्रयोजना के लिये 6 2, 3 1, 841 रुपये मांगे गये हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह भी सारा पैसा हिसार में ही खर्च करने जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह योजना बहुत अच्छी है इसलिये इसको हरियाणा के हर एक जिले में लागू किया जाए – (विध्न)––

चौधरी सन्त कंवर : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । मैं स्वामी जी को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि गुड़गांव और वल्लभगढ के इलाके में भी यह स्कीम चला रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं है ।

स्वामी आदित्यवेश : यह जो योजना है यह हर एक जिले के लिये बड़ी लाभकारी है । इसमें स्थानीय साधनों से रोजगार को बढ़ाना, गांव में लघु उद्योग स्थापित करना, पशुपालन को बढावा इतना, छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों की भलाई के लिये अच्छे प्रोग्राम बनाना तथा सैल्फ एम्पलायमैंट को बढ़ावा देने की बातें हैं । तो इस काम के लिये केवल हिसार को ही' क्या चुना गया । यह समस्या तो सारे हरियाणा में है इसलिये यह व्यवस्था हर जिले के लिये बनाई जाए न कि केवल हिसार के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष : स्वामी जी, जरा जल्दी खत्म करें ।

स्वामी आदित्यवेश : दो मिनट में समाप्त करता टू । मैं कह रहा था, डिप्टी स्पीकर साहब सरकार छोटे छोटे इन्टरप्रन्योर्ज को रुपया देना चाहती है ताकि वे ग्रामों में उद्योग– धंधे खोल सकें, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे गुडूगावा जिले में केवल एक यूनिट को रुपया दिया गया है जबकि सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में, अर्थात 31 मार्च, 78 तक 110 यूनिटों को पैसा देना है । बडे खेद की बात है कि हमारे जिले में 110 यूनिटों में से केवल एक यूनिट को दिया मझा । मैं चाहता हूं कि इस दिशा में तेजी से काम दरो ताकि जो नये इन्टरप्रन्योर हैं, उनको सहायता मिले । उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, मैं आपका धन्यवाद– करता हूं । (इस समय सभापतियों की सूची मेंसे एक सदस्य**चौधरी** ' खुरशीद अहमद पदासीन हुए)

चौधरी हरि चन्द हूडा : चेयरमैन साहब, लावारिस लाश को फूकने की जिम्मेवारी तो सरकार की है मगर मुझे ताज्जुब है कि सरकर ने एक्स–गवर्नर की लाश को फूकने के लिए 80 हजार रुपया खर्च करदिया । इतना रुपया खर्च करनेकी क्या जरूरत थी । जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि सिरसा, हिसार वगैरा इलाकों पर सरकार ज्यादा खर्च करती है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन की तरफ कम ध्यान देती है । इस तरह से फैवरेटीजम नही होना चाहिए । मेरा मकसद यह है कि कोई भी फैवरटीजम जब होता है तो वहीं से कुरप्शान शुरु होती है । मैं हाउस को कहूंगा कि कोई भी फैवरटीजम अगर हो तो उसको यही रोक दें! ऐसा होगा तो

हम हाउस से ही सारी कुरप्शन रोक लेंगे । अगर यहां फेवरटीजम होगी तो उमकी वजह से सब जगह कुरप्शन फैलेगी । (व्यवधान)

श्रीमूल चन्द जैन (सम्भालखा) : स्पीकर साहब, में डिंमाड नं. 3,7,8,17, 21, 9, 25 पर हाउस. के सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा । इन पर मैं विस्तार से कहना चाहूंगा, और देना चाहूगा और सरकार के नोटिस में लाना चाहूगा कि अगर सप्लीमेंटरी' बजट 10 हजार 20 हजार, 50 हजार या 2 लाख का हो तो मान लेते, चलो ठीक है, एक आईटम पहले से चली आ रही थी उस आईटम पर और रुपया खर्च होगा, यह नजरअन्दाज. किया जा सकता हैं लेकिन जब करने–रें रुपये का सप्लीमेंटरी बजट हो, जितना रुपया बजट में किसी आईटम के लिये रखा था उससे करोड़ों रुपया ज्यादा खर्च हो जाए तो बड़ा अफसोस होता है । मिसाल के तौर पर, बजटमें जितना रुपया सड़कों के लिए, बिल्डिग्ज के लिए मंजूर किया था उससे तकरीबन दुगना रुपया या दुगने से भी ज्यादा रुपया इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा मांग रहे हैं । लेकिन इस किताब में कहीं भी बता नहीं रहे कि. इस रुपये से कौन कौन सी सड़कें बन रही हैं, किस किस जिले में बना रहे हैं । इसमें तो नई सड़कें बनाने का भी जिक्र है लेकिन. यह नहीं बताया गया कि वे कहां बन रही हैं । मैं खास तौर पर यह कहना चाहूंगा कि यह हमारे साथ अन्याय है । आप हमसे करोड़ों रुपये की मन्जूरी लेना चाहते हैं और हमें यह भी बताएं कि नई सडकें कहा कहां बनने जा रही हैं इसमें स्कूलों को अप–ग्रेड करने का.

प्रश्न है लेकिन यह तो बताए ' कि कौन कौन से स्कूल को अप–ग्रेड़ कर रहे है । यह फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को बन्द हो जायेगा और आपके पास इस करोड़ो रुपये को खर्च करने के लिये सिर्फ 25 दिय रह जाते हैं और आप इन 25 दिनो में इतना रुपया खर्च नही कर सकते । जिस रुपये को आप मंजूरी ले रहे है या. तो पहले पहले खर्च कर चुके हैं, अगर कर चुके है तो पहले बतलाना चाहिए था और अगर खर्च नही किया तो क्या आप इन 25 दिनों में करोड़ों रुपये का खर्च कर सकेंगे, यह मेरी समझ. से बाहर की बात है यह मोटी सी बात मैं तमाम डिमांडज के बात्ए में कहना चाहता था।

अब मैं डिमांड नं. 3 पर जो पुलिस से सम्बन्धित है, बोलना चाहता हूं । पुलिस के लिए 6557930 रुपया मांग रहे हैँ । मैं सरकार सें जानना चाहूंगा ऐमरजैसीं खत्म हो गई है, अब' फालतू पुंलिस की क्या जरूरत है एमरजेंसी' के. जमाने में पुलिस पर ज्यादा जौर था सी0 आई0 ड़ी 0 करवाने के लिए, और तरह तरह की गलत बातें करवाने के लिये, लेकिन' अब तो वह काला–युग समाप्त हो गया, अब क्या जरूरत है पुलिस पर इतना रुपया खर्च करने की

सिंचाई तया बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : पिछला गन्द धोने के लिए है (व्यवधान) ।

श्री मूल चन्द जैन : यह तो स्टाफ भर्ती कर रहे है, यह गंद वाली बात बिल्कुल गलत है येहाउस को मिन–लीड कर रहे हैं । हम इस हाउस के अन्दर इस तरह का मजाक बरदाश्त नहीं करेंगे और न ही इस आवाज को उठाए बगैर रहेंगे । यह नया खर्चा पुलिस भर्ती करने के लिए लिया है ।

श्री सभापति : इतनी सख्त लैग्वेज इस्तेमाल न करें। I request you to withdraw the word 'mislead'.

श्री मूल चन्द जैन : आपका आदेश है इमको मानना मेरा कर्तव्य हो जाता है ।

Mr. Chairman : Misleading should be taken as withdrawn.

श्री मूल चन्द जैन : किसी आदमी के बारे में, सरकार के बारे में मिसलीडिंग कहना बिल्कुल अनपार्लियामेंटरी नहीं है । हां, मैं कह रहा था कि 6 5, 5 7, 930 रुपये का खर्चा पुलिस की मद में है और आपने इसमें बताया कि नये सिपाही भर्ती कर रहे हैं । आपको नये सिपाही भर्ती करने को क्या जरुरत पड़ गई, स्टेट में ऐसी कौन सी बातू हो गई है जो इतना खर्चा बढ़ाया है? बाकि स्टेट्स भी हैं, पंजाब है, दिल्ली है, यू 0टी0 है, उत्तर प्रदेश है, क्या इन प्रान्तों में भी पुलिस की नई भर्ती है, नया खर्चा है? चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि जिंतनी –सूचना इस किताब में हमारी सरकार ने दी है, वह नार–काफी है । आप हमें पूरी सूचना दे ताकि हम इस डिमांड पर पूरी तरह से गैर कर सकें ।

अगली डिमाड नं. 7 है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज जो लाटरी के बरे में है । बजट में 90 लाख रुपये के टिकट बेचने का प्रोंवीजन किया गया जिस पर 69 लाख रुपया खर्च करने का प्रोवीजन था । अगर सरकार 90 लाख के टिकट बेचे तो'उस पर 69 लाख रुपया छपवाई, इजहार और ईनाम देने पर खर्च करती है । क्यूं इस सपलीमेटरी बजट में 90 लाख की बजाए 96 लाख के टिकट बेचने की सूचना दी है यानी तकरीबन 6 लाख रुपया और बढ' गया है । इस 8 लाख पर खर्च कितना बढा है, वह हैं साढ़े है लौच रुपया । कमाल की बात है, आमदनी 8 लाख की होगौ, टिकट 6 लाख कें फालतू बिकेगें और टिकट छपवाई का खर्चा साढे अ लाख रुपया करने जा रहे हैं । अगर इस तरीके से सरकार का फिनांस चलेगा तो फिर हमारा खुदा हाफिज है । इसेके इलावा इसमें केवल छपवाई वगैरा का खर्चा दिखाया है । जो हमारे आई0ए0एस0 अफसर हैं, दूसरा स्टाफ है उसका खर्चा इस में दिखाया ही नहीं । 90 लाख के टिकट बिकते हैं हो सरकार की 2 1 लाख की आमदनी हुई । इस 21 लाख रुपये में 4— 5 लाख रुपया हमारें स्टाफ का है, इस गवर्नमैंट के आई0ए0एस0 आफिसर हैं जैसे सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी, अंडर सैक्रेटरी, सुपरिंटेंडेंट, असिस्टैटं और क्लर्क वगैरा है जो लाटरी का काम करने है और अगर इस 21 लाख की आमदनी में से इस स्टाफ का खर्चा भी घटाया जाए तो मुश्किल से केवल 15 लाख रुपये की आमदनी रह जाती है । चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकर से कहना चाहता हू, पहले भी मैंने कहा था कि इस जूए

की आदत को खत्म करें जिससे 1 5 लाख की आमदनी हो और खर्च ज्यादा हो, इससे कोई फायदा नहीं । मैंने अखबार में पढ़ा था, मेरे ख्याल में हमारी सरकार की ही बात होगी । लाटरी डिपार्टमैंट के कुछ अफसरान ने कुरप्शन की जिसकी बिनाह पर कुछ अफसरान सस्पैडं हो गए । मेरा ख्याल है हरियाणा सरकार के ही आफिसरों की बात है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पाप के खून में क्यों हाथ रंग रहे हो । सरकार को लाटरी के काम को बन्द कर देना चाहिए ।

चेयरमैन साहब, अगली बात बड़ी इम्पौटेंट है, जैसा कि परसों हाउस में सड़कों का जिक्र आया, बहुत से सदस्य इस मामले पर एजिटेट हो गए थे । 3 करोड़ 70 लाख रुपया बिल्डिग एंड रोड्ज के लिए बजट में मन्त्री थी और अब हमारी सरकार 4 करोड़. 90 लाख रुपये सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा और लेना चाहती है । इस तरह कुल मिलाकर बिल्डिग एंड रोड्ज के लिए 8 6 करोड़ स्पया हो जाता है । मैं मन्त्री महोदय का खास तौर पर ध्यान खीचना चाहता हूं कि हरियाणा के 90 हलके है । अगर एक एक हलके में दस दस लाख रुपया खर्च करें तो मुझे बड़ी खुशी है । टोटल रुपया तो 8. अ करोड़ खर्च होगा, इसके इलावा और रुपया है वह भी खर्च होगा । क्या यह हाउस और जनता पार्टी के सदस्य और मिनिस्टर साहब, अपने सीने पे हाथ रख कर कह सकते हैं कि हर एके एम 0एल0ए0 के हलके में, यानी 90 हलकों में दस दस लाख रुपया खर्च किया गया है? अगर किया है तो

हमें बहुत खुशी है और जो रुपया आप सप्लीमेटरी बजट' में 4. 9 करोड माग रहे हैं, क्यकी मन्जूरी जरूर देंगे लेकिन अगर वह रुपया जैसा कि परसो कें स्टेटमैंट से जाहिर होता है 20 सडको पर हिसार में, 25 सड्कों पर दूसरी जगह यानी 8. करोड में से आधे से ज्यादा रुपया तीन जिलों में या दो जिलों में खर्च करना है तो मैं मन्त्री महोदय को और खजाना मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि पार्टी डिस्पलिन के महत जो हम इसकी मंजूरी वेदेने लेकिन हमारे मन को शांति नहीं होगी और यह आवाज हम हाउस में भी उठाएगे और बाहर भी कहेंगे कि यह सरकार रुपये की तकसीम गुना– सिब ढंग सेनहीं कर रही है । पिछली कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा किया था अभी वीरवार को मार्किट कमेटियो के बारे में प्रस्ताव हाउस में आया था । मैं समझता हू कि यह जो 9 करोड़ रुपया स्पलीमैंटरी डिमांडज में सरकार ले रही है इक्के क्य मार्किट कमेटियों का काफी रुपया शामिल है । तो मै सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस रुपये को इसलिए इसमें शामिल किया गया था कि कप इस रु क्के कों –झन्– हल्कों में क्यम्बर तकसीम व करके कुछेक हल्को में खर्च करें? कांग्रेस सरकार क्या कोई अगर क्रेडिट देना हो तो एक क्रेडिट जरूर दिया जा सकता है । उन्होंने अगर बिजली कई तो हरियाणा के एक एक गांव में दी इस बात की तमीज नहीं की कि बंसीलाल जी के हल्के में बिजली चली गई, पोसवाल साहब के हल्के में बिजली चली गई लेकिन चौधरी शिवराम, जो उस समय अपोजिशन के मैम्बर थे, के हल्के में बिजली नही गई । तमाम स्टेट में उन्होंने

बिजली दी । इसी तरह उन्होंने सड़के दी । 80 फीसदी सड़कें के कांग्रेस सरकार के जमाने में ही बन चुकी थी । उन्होंने इस तरह की बात नहीं की । यह हो सकता है कि किसी हल्के में 75 फीसदी सड़कें बनी हो और किसी में 85 फीसदी बनी हों । पांच दस परसैन्ट का मार्जिन तो हो सकता है । इसलिए मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से खास तौर पर यह कहना चाहता हू कि यह फर्क न करो कि एक हल्के में तो कुछ नहीं और दूसरे हल्के में सब कुछ । हम करनाल और अम्बाला में ऐसा महसूस करते हैं कि विकास का काम नहीं हो रहा है । आप भले ही कार्य करते होंगे लेकिन हम उस कार्व को अपने हल्के में होने वाले कार्य से नापते हैं । हम देखते हैं कि हमारे हल्के में आप क्या कर रहे हैं । पानीपत, घरौंडा, इन्दरी और नीलोखेडी में क्या हो रहा है । मैंने उस दिन भी इस बात पर जोर दिया था और आज भी बहुत अदब लेकिन दु:ख के साथ कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े हमें दिए हैं और जो कुछ इस बजट से जाहिर होता है, वह अगर आपने ठीक तकसीम किया है, तो आपको इसी में बता देना चाहिए कि इतना रुपया करनाल में दिया, इतना अम्बाला में दिया और इतना फलां जगह दिया ताकि हर सदस्य यह कह सके कि हमारी सरकार की जो आमदनी है, जिस रुपये की हम हाउस में मंजूरी देते हैं, वह सारी स्टेट में बराबरी के तौर पर तकसीम हुई है ।

चेयरमैन साहब, इसी सप्लीमेंटरी बजट में एक डिमांड नम्बर 17 है । उसमें भी रेगिस्तानी इलाकों में विकास के लिए

भारत सरकार ने 1 35 करोड़ रुपया दिया है । वह बहुत खुलीकी बात है । हमारे हरियाणा में सिरसा, महेन्द्रगढ़ और भिवानी रेगिस्तानी इलाके हैं । उस सज जब मार्किट कमेटियों का जिक्र आया तो कई सदस्यों ने कहा कि उन इलाको केलिए रुपया चाहिए और अगर सम्भालखा या पानीपत की मार्किट कमेटियों की स्वय।. सवर खर्चे हो' जाए तो मुझे गिला नहीं करना चाहिए 'लेकिन मैं उन दोस्तों और मन्त्री साहब से कहना चाहता हूं इन रेगिस्तानी इलाकों के लिए तो 1. 35 करोड रुपया खास तौर पर मंजूर हुआ था हू इसमें 'से न तो आप पानीपत को देंगे, न धरोंडा को देंगे और न किसी दूसरी जगह को देंगे हू (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप रेगिस्तान उधर ले जाओ ।

श्री मूल चन्द जैन : आप हमारी तकलीफ को भी समझें । ऐसा न करो । 1 करोड़ 35 लाख रुपया खालिस रेगिस्तानी इलाके के लिए मिला है । इसमें से एक कौड़ी भी आप हमारी सड़कों के लिए नहीं देंगे । हम मांगेंगे भी नहीं । जब ऐसा है तो हमारी आमदनी में से वहां क्यों खर्च हो । हमारा किसान, हमारा देहाती, जो गन्ना, गेहूं और चावल पैदा करता है उसे वह मंडियों में बेचता है । तो उस सभालखा के रुपये, पानीपत के रुपये और घरौंडा के रुपये पर आपका क्या अधिकार है कि उसे आप भिवानी में खर्च करें सिरसा में खर्च करें या हिसार में खर्च करें । श्री बंसी लाल के पर यह भी एक आरोप था । आप क्यों इस आरोप

के भागी बनते हो । आप इन्साफ कीजिए । तभी आप इस स्टेट के मुख्य मंत्री या मन्त्री कहला सकते हो ।

चेयरमैन साहब, इसी तरह का तीस लाख रुपया और है । वह इस मद में नहीं है बल्कि आगे एक मद है कम्युनिटी डिवैल्पमैंट की, उसमें है । इसके भी दो हिस्से किए हैं । एक हिस्से में 30 लाख रुपया है जो देहाती लिंक रोडज के लिए है । उस दिन बड़े कैरव. के साथ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि चूंकि पंजाब के विलेजिज को मिलाने के लिए. सड़कें दे रहे हैं इसलिए हिसार को ज्यादा सड़कें मिल गई और मुझे गिला नहीं करना. चाहिए । ये सडके तो पंजाब के गांवों को मिलाने के लिए नहीं हैं । यह पैसा तो हमारी स्टेट के जो कम्युनिटी डिवैल्पमैंट प्रोजैक्टस हैं उनके लिए हिन्द सरकार ने दिया है । यह आपका रुपया नही है । इस हिन्द सरकार के पैसे को आप क्यों छिपा कर रख रहे हे? क्यों नही बताते कि कौन कौन से लिंक रोड आप बनाएंगे । यह भी कोई बात हुई कि हम तो तीस लाख रुपये की मंजूरी दे दें लेकिन आप हाउस को यह भाई न बताए कि कौन, सी सड़क कहां बनेगी? जब बजट खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : बाबू जी, क्या आप बताया करते थे?

श्री मल चन्द जैन : जी हां ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : पिछला रिकार्ड निकालेंगे । (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन : अगर मैंने निकम्मे काम किए तो क्या आप भी निकम्मे काम करेंगे?.(विघ्न)

Mr. Chairman : You make some reforms in the previous record.

श्री मूल चन्द जैन : हम तो चाहते हैं कि आप अच्छे कामं करें । हम 'अच्छा काम करने में आपको पुरजोर सहयोग देंगे । (विघ्न)

इसके बाद, चेयरमैन साहब, मैं ऐजुकेशन की डिमांड नम्बर 9 पर– कुछ कहना चाहूंगा । इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि टीचर्ज का रुका हुआ डीयरनैस अलाउंस देकर के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है । इसी तरह से कुछ अन्य लोगों का भी डीयरनैस अलाउस इन्होंने बहाल किया है वह भी बहुत अच्छा काम है । लेकिन यह जो स्कूल अपग्रेड़ करने के लिए ओर 10+ 2 + 3 पता नही यह क्या बला है, मैं लैबोरेटरीज और लाइब्रेरीज स्ट्रेन्गथन कैदने के लिए 7 4, 4 5, 345 रुपये की मांग कर रहे हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आई । – (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह : बाबू जी अब तो काफी हो गया, बजट पर भले ही 8 घंटे बोल लेना । (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, मैं तो आपके जरिए सरकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं कि वे भी अपने काम को अच्छे ढंग से करें । वे फाईल में लिखे कि इस तरीके से

तकसीम नही होनी चाहिए । इस सरकार के जो फाईनैन्स सैक्रेटरी और डिप्टी सैक्रेटरी हैं उनसे मेरी यह शिकायत है । वे क्यों नहीं देखते कि इस तरह दो आइटम्ज को क्यों मिलाया गया? क्या यह नेकनीयती है? बिल्कुल गलत बात की गई है । हमें कैसे पता लगेगा कि 7 4, 4 5, 345 रुपये में से स्कूल अपग्रेड करने के लिए कितने रुपये खर्च होंगे. और कितने रुपये दूसरे काम के लिए खर्च होंगे । क्या यह इनकी ड्यूटी नही थी कि हमें बताए कि इतना रुपया हम स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए खर्च करेंगे और फलां जिले में फलां स्कूल आपग्रेड होगा । चेयरमैन साहब, मैं मंत्री महोदय से और कैबिनेट से यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार हमारे किसान, व्यापारी और मजदूर के जमा किए हुए रुपये को इन्साफ से बांटेगी तब तो हम इसकी मंजूरी देंगे और अगर नहीं बांटेगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे । अब भी मैं चाहूंगा कि ऐसा न किया जाए । उस रोज ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब से जब सवाल पूछा गया कि कौन से स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं तो कहा गया कि अभी लिस्ट नहीं बनी । ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यह इस बात को छिपा कर रखना चाहते है । मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैए । इनको बिल्कुल साफ तौर पर हाउस के सामने बात बतानी चाहिए । (विघ्न) –

Mr. Chairman : Please do not interfere. Let him finish.

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, अब मैं एक आइटम के पर अपनी बात कह कर अपना स्थान ले लूगा । चेयरमैन साहब, यह केवल मेरे हल्के की शिकायत नही हे वल्कि एक जनरल शिकायत है । जंगलात के महकमे को 36 67 लाख रुपया तो हिन्द सरकार ने दिया कि पंचायतों की जितनी भी जमीन पड़ी है उस पर वृक्ष लगें । इसमें तो हमारा फायदा है । यह पैसा तो हिन्द सरकार से आ गया लेकिन इसके अलावा 35 लाख रुपया सरकारने हम से और लेना है । 38. 6? लाख अलग है और 35 लाख अलग है ।

यह रुपया आप खर्च कर चुके है या अभी करना है यह इस किताब में नहीं बताया है । आपको बताना चाहिए था कि कहां खर्च करना चाहते हैं । इस प्रकार से सप्लीमेटरी डिमान्डज पेश नहीं की जाती हैं । आप को हाउस की तसल्ली करानी चाहिए कि कहां– कहां पर खर्च करना चाहते हैं । इसी प्रकार से इन्डस्ट्री विभाग ने भी 25 लाख रुपया मांगा है । स्वामी आदित्यवेश जी ने तो एक और ही स्कीम बता कर इस बात को कनफ्यूज कर दिया । वह 1 10 लाख रुपया है । यह चार परसैन्ट के हिसाब से गालबन दिसम्बर में भारत सरकार से आया है । इस रुपये को भी अभी बांटना है । तो मैं चाहूंगा कि इन्डडी मिनिस्टर और वित्त मंत्री जी ठीक प्रकार से बांटें । चार परसैन्ट सूद बहुत कम है । यह पैसा देहातों में दस्तकारी के लिए, पढे–लिखे लोगों के लिए देना है ।

तो मैं चाहूंगा कि यह रुपया न्यायपूर्ण ढंग से तकसीम करना चाहिए । यह चीज मैंने कैबिनेट के सामने रखी है।

रोहतक यूनिवर्सिटी के लिए 23 लाख रुपया पहले से बजट में था । अब 27 लाख रुपया और ले रहे है । तो इस सप्लीमेंटरी में 27 लाख रुपया जो आया है यह रुपया आप पहले ही खर्च कर चुके हैं या बीस दिन के अन्दर खर्च करना चाहते है । बड़ी मोटी सी बात है और मैं तो बड़ा परेशान हूं कि इतनी बड़ी बड़ी रकम है, आज छरू मार्च हो चुकी है किस प्रकार से इस पैसे को खर्च करेंगे? कहीं लूटा रेंगे, क्या करेंगे? इस बारे में फाइनेन्स मिनिस्टर को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । इन्डस्ट्री मिनिस्टर और इरीगेशन मिनिस्टर साहब भी इस ओर ध्यान दें । जैसे स्कूलों की अपग्रेडिंग का मामला है । हर जिले के अन्दर, तहसील के अन्दर न्यायपूर्ण तरीके से तकसीम किया जाना चाहिए ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : (पाई) चेयरमैन साहब, मैं ज्यादा तो बजट पर बोलना चाहता हूं इसलिए इस समय तो आपसे मैंने केवल दो मिनट ही मांगे है । हमारे बुजुर्ग पुराने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो बातें यहा हाउस के सामने रखी हैं उनके बारे में मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं । जनता पार्टी में होते हुए भी उन्होंने बड़ी इंसाफ की बातें कही हैं । इसलिए मैं तो एक दो आइटम पर ही बोलना चाहता हूं । एक डिमान्ड से स्टैन्डर्ड का पता चल जाता है । पके हुए चावलों में से एक दाना

निकाल कर देखने से सभी चावलों का पता चल जाता है । इसलिए चेयरमैन साहब, आपने खुद भी यह क्वैश्चन पूछा था कि सारी की सारी सड़के सिरसा और हिसार में बनायी जा रही है, वही बात मेरी है । हर आइटम का यही हाल है, सारा का सारा पैसा किसी न किसी ढंग से वहीं जा रहा है । जैसे डिमान्ड नम्बर 8 रोडज की है । दो ही जिलों में सारा पैसा जा रहा है । चौधरी बंसी लाल भी हमारे साथ सौतीली मां का सलूक करते थे सारा का सारा पैसा अपने इलाके में लगाते थे, वही हालत जनता सरकार की हो रही है । हम तो समझते थे कि जनता सरकार इंसाफ देगी, सब के साथ बराबर का व्यवहार करेगी लेकिन There must be some principal for distribution of the money for the development of work in every constituency.चेयरमैन साहब हमारे 90 हल्के हैं, सब हल्कों में बराबर का पैसा बांटा जाये ।

इतना जुल्म सहन नहीं किया जा सकता । इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जैसा जुल्म हमारे साथ पहले होता था वैसे। अब न करें ।

श्री सभापति : इक्यीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन होनी चाहिए ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : बिजली में बराबर की डिस्ट्रिव्यूशन होनी चाहिए । आप लोग भी पिछली सरकार की कार्यवाही पर न चलो । पिछली सरकार ने तो सबक ले लिया । जनता ने उनसे कुर्सी छीन कर आपको दी है, जब आपकी सरकार आयी है तो ये सड़कें खाली हिसार और सिरसा के लिए ही न

बनाओ वरना आप का भी वही हाल होगा । 90 हल्के है सब ये बराबर का पैसा बाटो । 1 0 1 5 दिन में इतना पैसा आप लोग कैसे लगायेंगे? **चौधरी** सतवीर सिंह मलिक किसान का बेटा है, फाइनेन्स डिपार्ट– मैट इनको मिला है लेकिन अफसोस इस बात का है कि वह खुल कर बात नहीं करता है? उनको सारे पैसे का बराबर का बंटवारा करना चाहिए । जाट कालेज में साय पढ़ा है, उस कालेज में गरीब किसानों का खून–पसीने की कमायी का पैसा लगा है । मैं तो उनसे कहूंगा कि किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है । लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हिसाब से पैसा खर्च करें । जैसा कि मूलचन्द जैन जी ने कहा है कि सारा पैसा एक जगह पर न लगायें । यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ।

अब मैं लाटरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । लाटरी तो एक प्रकार का जुआ है । अगर किसी गांव में लोग ताश खेलते हुए मिल जायें तो पुलिस अफसर उन पर जुये का केस बना देते है लेकिन यहां तो सरकार खुद जुआ खिला रही है । इसलिए लाटरी भी जुआ है, इसको बन्द किया जाना चाहिए । मैं क्या–क्या आपसे अर्ज करूं यही हालत फोरेस्ट डिपार्टमैंट की है । हर डिमान्ड में बराबर का बंटवारा होना चाहिए तभी आपका काम ठीक चलेगा । चेयरमैन साहब, मैं खुल कर तो बजट पर बोलूंगा । इसलिए इन डिमान्डज के बारे में कुछ नही कहता । हां

इतना जरूर कहूंगा कि बैकडोर से पैसा न लो सीधे मैदान में आ कर खर्च करो ।

सरकार ने श्री चक्रवर्ती के मरने पर कितने पैसे खर्च कर दिये, हमारे बूढ़े मरते हो कोई इतना पैसा खर्च नही करता । हमारी सरकार ने तो उनके मरने पर पैसा लूटा दिया हे । चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाईम दिया । कल आप मुझे पूरा टाईम दे देना ।

श्री रघुनाथ गोयल (कैथल) : चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए शिक्षा मंत्री महोदय से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे सिंचाई मंत्री महोदय ने कहा है कि एक एम 0एल 0ए 0 चार चार गांव का नाम दे दे सड़क बना देंगे । इसी तरह से शिक्षा मन्त्री महोदय भी चार–चार या दस–दस गांव के नाम मांग लें, उनमें स्कूलों को अपग्रेड कर देवे । हस प्रकार से हर हलके में काम हो जायेगा ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : (बादली) रू चेयरमैन साहब, अभी अभी हमारे साथी ने यहां हाउस में कहा है कि पैसे की बराबर की डिस्ट्रिव्यूशन हो ।

श्री सभापति : आप डिमान्ड नम्बर बताएं जिस पर आप बोल रहे कद ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : मैं क्त मैम्बरों से यह अर्ज करना चाहता हूं जो यह डिमान्ड करते हैं कि बराबर की

डिस्ट्रिब्यूशन करो । जब फल्ड में हमारे लोग मरने लग रहे थे, तबाह होने लगू रवे थे, सडके' टूटने लग रही थीं, बिल्डिगे गिरने लग रही थीं, तब इन मैम्बरों ने भगवान् से यह प्रार्थना क्यों नही की ड़िय यह आफत हमें भी बराबर वे दो । इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से वह कहूंगा कि मेरा सारा हल्का सब से ज्यादा बरबाद हुआ पड़ा है । हालात को और मजबूरियों को देखकर डिस्ट्रिब्यूशन करनी चाहिये ।. (विघन).. एक सैकिण्ड में मैं एक बात और कहकर बैठ जाता हूं । इसमें जो रुपया खर्च करने की बाबत लिखा हुआ है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक्य प्रया है कि मार्च के आखिर में सरकारी ग्रान्टें महकमों को मिलती है और वह जल्दी मे पैसा खर्च कर देते हैं । मेरा कहना यह है कि वह रुपया बिल्कुल सही मायनों में खर्च नही हो पाता । इसलिए जो भी रुपया महकमों को मिले, उसके लिये उन्हे इतना पीरियड जरूर दिया जाना चाहिये कि वह उस पैसे को ठीक तरह से प्टेनाईज/इस्तेमाल कर सकें । इस सिस्टम में सुधार करने की ओर मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि उसे अवश्य ही ध्यान देना चाहिये । मैं सरकार से चेयरमैन साहब, आपके द्वारा यी अर्ज करूंगा कि जो पुरानी प्रथाएं हैं, उनको दफना दे ।

श्री दीप चन्द भाटिया (फरीदाबाद) : चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा

श्री सभापति : आप यह भी देख लें कि कौन सी. डिमान्ड के बारे में बोलना चाहते हैं । आप मुझे पहले सज्बैक्ट बता दीजिये ।

श्री दीप चन्द भाटिया : मैं जनरल बात करूंगा ।

श्री सभापति : वह तो बजट पर ही हो सकेगी । वहतो सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्म हैं, अगर सड़क के बारे में बोलना चाहें तो डिमान्ड नं 0 8 ले लीजिये ।

श्री दीपा चन्द भाटिया : चेयरमैन साहब, आपके दवारा मैं सरकर से यह पूछना चाहता हूं कि हमारा फरीदाबाद एरिया जो कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है, जहा. से हरियाणा को सबसे ज्यादा आमदनी होती है, जहा से हरियाणा के लिये सबसे ज्यादा पैसा आता है, लेकिन इसके बाबजूद भी हरियाणा का वह इलाका जो बल्लभगढ–फरीदाबाद की कास्टीचूएसी के अन्दर आता है, क्यों उसको इग्नोर किया जाता है? मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जब सबसे ज्यादा आमदनी फरीदाबाद से आती है तो ज्यादा पैसा फरीदाबाद जोकि एक इडस्ट्रियल टाउन है, के पर लगाना चाहिये ।

श्री सभापति : डिमान्ड नम्बर तो बता दीजिए ।

श्री दीप चन्द भाटिया : रोड्ज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हू कि मेरे इलाके के अन्दर जो 29 गांव है, उनके अन्दर कोई रोड ठीक नही है, रास्ता कोई ठीक नहीं है । वहां पर

रास्ते बिल्कुल खराब हैं । (विल). मैं आपके जरिये हाउस को यह बताना चाहता हूं और ,मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं उनको यह भी बताना चाहता हूं कि अढ़ाई महीने हो गये उन्होंने झाडू सेतरी के अन्दर ' एक बस अड्डा के लिये मैनेजर को एक चिट्ठी लिखी थी कि यहां पर सब बसे खड़ी होनी चाहिये । लेकिन जनता सरकार के अन्दर मिनिस्टरों की हालत देखकर मैं हैरान हूं कि इनके आर्डर्ज कोई भी आफिसर नहीं मानता है । यहां पर श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं । मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि वह इनके आर्डर थे । जनता सरकार के अन्दर अगर वह इतना या काम भी नहीं करवा सकते तो मेरे विचार में इनको इस्तीफा दे देना चाहिये ।

Mr. Chairman : Shri Ganga Ram Please refer, to the demands first on which you want to speak ?

चौधरी गंगा राम : (गोहाना) चेयरमैन साहब, मैं डिमान्ड नं. 3 पर बोलना चाहता हूं । डिमान्ड नं 0 3 के अन्दर जो मांग रखी गयी है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस खर्चे की मांग रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी स्टेट के अन्दर जो सी.आर.पी. के नौजवान हैं, उनकी कोई आवश्यकता नही है । मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बोझे को दूर कर दिया जाये । सी0आर0पी0 पर जितना रुपया खर्च किया जाता है, अगर यह खर्चा खत्म कर दिया जाये और इसकी जगह हरियाणा के नौजवानों को पुलिस के अन्दर ले लिया

जाये तौ मैं कहूंगा कि यह बेहतर होगा । इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि इस डिमान्ड की जो इस समय हाउस में रखी गयी है, फिर इसकी कोई आवश्यकता नही पड़ेगी । दूसरे इससे हमारी स्टेट के जितने नौजवान है, उनको रोजगार भी मिलेगा और इससे स्टेट की बहुत अच्छी तरह से भलाई भी हो सकेगी । इसके अलावा मैं डिमान्ड नं. 7 के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसज के लिये यह जो खर्चा मांगा गया है, मुझे हैरानगी है यह देखकर कि जो बजट पेश किया गया है उम बजट के अन्दर एडमिनिस्टेरटिव सर्विसिज के लिये एप्रोक्सिमेट एक्सपैडीचर जो है वह 27 करोड रुपया रखा गया है । मैं हैरान हू कि जब बजट के अन्दर इस डिमान्ड के लिये 27 करोड़ रुपया रखा गया है तो सप्लीमैंटरी डिमान्डज में वहकैसे आ गयी । मैं अपनी सरकार को यह बताना चाहता हूं कि एडमिनिस्टेरटिव सर्विसिज के लिये जो खर्चा किया रहा है वह एग्रीकल्चर से लगभग दुगना खर्व किया जा रहा है । हरियाणा सरकार का एप्रोक्सिमेट एक्सौडीचर एग्रीकल्चर के अन्दर मुश्किल से 19 करोड़ रुपये है जबकि एडमिनि– स्ट्रेटिव सर्विसिज के लिये 27 करोड़ रुपये हें । तो मैं सरकार को यह सुझाव दूंगा कि आज हरियाणा के अन्दर आप जाकर किसी भी आफिस में देख लें, हमने तो देखा है कि एक एक आफिसर के पास एक–एक दफतर में 3–5, 4– 4 जीपे हैं और हजारों रुपयों का पैट्रोल उनमें फूंका जाता है और हजारों रुपया उनकी मुरम्मत के लिये लग जाता है ।

यही नहीं एक–एक अफसर के लिये 3– 3 लाख रुपये की कोठियां बनायी जा रही हैं । कम मैं मैडीकल कालेज रोहतक के अन्दर गया । तो मैं हैरान हो गया जब मुझे रजिस्ट्रार थे यह बताया कि. जो एक कोठी यहां पर एक डाक्टर को दी गयी है, उस पर 3 लाख रुपक खर्चा आया है । इसलिये मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जो 'द्र' खर्चा किया जा रहा है, गाड़ियों के पर, प्रैट्रौल के पर, उनकी मेनटैनैस के पर, यह सारा का सारा जितना खर्चा है, अगर सरकार इसको हटा दे तो इस डिमान्ड की आवश्यकता ही नही पड़ेगी ।

कंवर राम पाल सिंह : चेयरमैन साहब, यह यह ..... . अनपार्लियामैट्री है, इसकी कार्यवाही में से निकालना चाहिये ।

चौधरी गंगा राम : इसमें अनपार्लियामेंटरी कुछ भी तो नही है ।

Mr. Chairman : Behuda word should be expunged.

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, मैं 'किसी आफिसर के खिलाफ नहीं हूं और मैं यह चाहता हूं कि आफिसरों को पूरी सहूलियतें मिलती चाहिये । लेकिन मैं यह कहता चाहता हूं कि जो अननसैसरी खर्चा है, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता नही है, वहां पर वह नही होनी चाहिये इसलिये मेरा कहना यह है कि हये ऐसी डिमान्ड रखने की बजाये इस तरह का खर्चा घटाना चाहिये । हमारे आफिसर्ज ही सही बल्कि हस जो पोलिटीशयन्ज और जो

हमारे मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए है, उनको मिसाल कायम करनी चाहिये । मुके यह देखकर बड़ी हैरानगी होती है कि एक मिनिस्टर पर हरियाणा सरकार का करीब 9 हजार रुपया मन्थली खर्चा आला है ।

Mr. Chairman : Please take up this point when you speak on the budget. Limit your speech at the moment to the grant under discussion.

चौधरी गंगा राम : तो चेयरमैन साहब, सैं यह कहना कक्का हूं कि डिमान्ड नं. 7 को घटाया जा सकता था अगर हम इस तरह के खर्च कम कर देते इसके अलावा सैं डिमान्ड नं0 16 जिसमें पब्लिक वर्कस, एजूकेशन और कम्युनिटी डिवैलपमैंट का मसला आया है, इसके बारे में भी बोलना चाहता हूं । मैं के हैरान हूं कि कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट के बारे में, पब्लिक हैलथ के बारे में और पब्लिक वर्कस के बारे में जितनी ड़िमान्ड रखी रायी है उसके बारे में यह लो बताया गया कि पब्लिक वर्कस के लिये जितना रुपया चाहिए, कस्यू निटी डिवैलपमैट के लिये इतना चाहिये, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि रूरल एरियाज जो है। वहां पर कितना पैसा खर्च होगा, और अर्बन एरियाज के अन्दर कितना पैसा खर्च होगा । इसलिये मैं यह चाहूंगा कि हमें इसकी डिटेल खोलकर आईटमवाईज बतायी जायें । हम हैरान हैं कि हरियाणा के अन्दर प्राइमरी एजुकेशन लो है, उससे हरियाणा सरकार को 9 नाथ रुपये की बचत होती है । एक तरफ तो हम कहते हैं कि फी ऐजूकेशन हो

Mr. Chairman : Mr. Ganga Ram, please wind up now because a very little time is left.

चौधरी गंगा राम : : चेयरमैन साहब,अगर इस समय थोडा टाईम है तो आप बजट पर हमे ज्यादा टाईम दें। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सप्ली– मैन्टरी डिमान्डज से कुछ तो जायज हैं लेकिन मोस्टली ऐसी है कि अगर आइन्दा इस तरह की डिमान्डज लाते रहे तो हरियाणा के कमेरे की कमर टूट जाएगी औत किसान. की मेहनत की कमाई, अगर आप कहीं और लगाते रहे तो यह हरियाणा के किसान के साथ जुल्म होगा । सरकार को अपना खर्च घटाने की कोशिश करनी चाहिए । इतना ही कहकर मैं खत्म करता हू ।

श्री शमशेर सिंह (नरवाना) : चौयरमैन साहब मैं आइटम नम्बर 7 जो है उस पर बोलना चाहता हूं । इसमें लिखा है

"The expenditure relating to the Punjab and Haryana High Court is shared proportionately among the Governments of Punjab; Haryana and U.T. Administration Chandigarh. Haryana's share in this expenditure has been raised from 29.14% to 31.95% .... .."

चेयरमैन साहब, मैं पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के बारे मै कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पंजाब तथा हरियाणा के कुछ और कामन लिंक हैं उसी तरह से हाई कोर्ट भी एक कामन लिंक है । जिस वक्त हरियाणा और पंजाब की रिआर्गेनाइजेशन

हुई उस वक्त चालीस और साठ का फार्मूला रखा गया था और बंटवारे की जो कामन बातें थीं उनमें चालीस और साठ की रेशो लागू हुई । लेकिन जहां तक पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट के स्टाफ तथा हाई कोर्ट के जानों की नियुक्ति का सवाल है वहां चालीस और साठ का फार्मूला कभी भी ऐन्फोर्स नही किया । मैं कह सकता हू कि जो हाईकोर्ट का स्टॉफ है उसमें रजिस्ट्रार से लेकर नीचे चपरासी तक का जो सैकड़ों की तादाद में स्टाफ है उसमें शायद हरियाणा के पांच परसेन्ट भी आदमी नहीं हैं और जहां तक जजिज का सवाल है पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में जूजिंज की गिनती हरियाणा साइड से बहुत कैम है । अभी पिछले दिनों हरियाणा तथा पंजाब हाई कोर्ट में पांच जंजिज की जगहे खाली थी और हाई कोर्ट में यह आम चर्चा थी कि उसके लिए हरियाणा से एक भी जज के लिए किसी आदमी कौ नाम रिकमेन्ड नहीं किया गया । चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जस्टिस डी0 बी0 लाल जो हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट के जज थें एमरजैन्सी के दौरान वहां से तबदील किये गये थे । एमरजैन्सी के खत्म होनें पर जब वे वापिस आए तो हिमाचल प्रदेश में जो आदमी उनके. स्थान पर लगा हुआ था उसने उनकी जगह खाली करने से इन्कार किया और श्री डी0 बी0 लाल को यहां पर पोस्ट कर दिया और वह जगह जिस पर हरियाणा का हिस्सा था उस खाली जगह के लिए यह निर्णय लिया गया कि जो हरियाणा की स्थान खाती है उस पर इन जज महोदय की नियुक्ति कर दी जाए । चेयरमैन साहब, में सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता

है कि यह सरकार हरियाणा कैं हित की बड़ी लम्बी चौडी बातें करतीं है । जिस तरह हर फ्रंट के पर– आज हरियाणा के हकूक बहूत बुरी तरह नजर अन्दाज किए जा रहे हैं उसी तरह हरियाणा. तथा पंजाब हाई कोर्ट के अदारे में भी हरियाणा के हकूक की बात करने के लिए सरकारे के कान पर जूं नहीं रेंगती । मेरा कैहना हैकि हाई कोर्ट 'कें मिनिस्टीरयल स्टाफ औरैं जजिज की नियुक्ति में चालीस और साठ की जो रेशो है उसको ऐन्फोर्स करवाया जाए । सरकार को हाईकोर्ट के मोहतरिम जजिज के साथ और गवर्नमैंट आफ इंडिया के साथ इस बात को टेक–अप करना चाहिए और हरियाणा के साथ जो वेइन्साफी हुई है वह खत्म करवानी चाहिए । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा की हाई कोर्ट अलग से बन जाए इस बात परं – गम्भीरता से विचार करना चाहिए । अगर हरियाणा की हाई कोर्ट अलग बन जाए तो हरियाणा के लोगों को न सिर्फ सस्ता इन्साफ मिल सकेगा बल्कि हरियाणा के हितों की पूरी तरह से रक्षा. हो सकेगी ।

वित मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : चेयरमैन साहब, जो 'सारी सप्लीमेन्टरी डिमान्डज हैं वे 1410 करो डु रुपए की हैं जिसके अन्दर 574 करोड़ रुपए की सैन्ट्रल अस्सिटेन्स है और इस सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूंकि यह ग्रान्ट उसी वक्त पेश हो सकरी है जब सेन्ट्रल गवर्नमैंट की असिस्टेन्स इसके लिए मिल जाए । ज्यों ही सैन्ट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस की मन्जूरी मिंत्री है मैं इस सदन के अन्दर 5–74 करोड़

रुपए की माग पेश कर रहा हूं । इसके अन्दर कुछ चार्ज्ड आइटम्ज थीं और बाबू मूल चन्द जी उनके पर बोले थे । इसमें सब से पहलो डिमान्ड नम्बर तीन थी. । इसके अन्दर एक सिपाही को डिकीटल अमाउन्ट की पेमेन्ट की जा रही है । यह 1963 का केस है और पिछली सरकार के जमाने का केस है । हम तो जो हाई कोर्ट का हुक्म है उसका पालन कर रहे हैं । इसी तरह से इसके आगे भूतपूर्व गवर्नर के फयूनरल की बात आई है वह भो पुरानी सरकार का किया हुआ खर्च है । इसके बारे में बाबू. मूल चन्द जी ने कहा कि यह रुपया– पुरानी केबिनेट से वसूल कर लिया जाए । चेयरमैन साहब, मरने वाला तो है कर गया और जो खर्चा भी था वह खर्चा भी हो गया और कुछ साथी जो पास करब। ना .३–– चाहते थे वह भी हमारें पास आ गए हैं अब यह बात अच्छी नही लगती कि पुरानी केबिनेट से वसूल किया जाए ।.

श्री शमशेर सिंह : आप यह बता. दीजिए कि डैड बाडी कें।' हवाई जहाज से लाने. में जो खर्चा हुआ यह वह रकम है ।

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : अब **चौधरी** शमशेर सिंह भी नहीं चाहते कि वह' वसूल किया जाए । यह खर्क डैड बाडी को 'लाने पर खर्च दुआ था । इसके बाद सदस्यों ने रोड्ज के वारें में शौर किया– लेकिन मैं आदरणीय बाबू मूल चन्द जी को बताना चाहता हूं कि 4 90 करोड़ रुपया जो है इममें से तीन करोड सैन्ट्रल असिस्टेंस का मिला है और यह अमिस्टेंस भी फलड एकेक्टिड एरियाज के लिए मिंत्री है । जहां कोई ग्रान्ट

स्पेशल परपज के लिए मिंत्रीं हो ढस्के बारे में मूल चन्द जी का यहं कहना कि किसी के साथ जुल्म हुआ है यह गल्त बात है । यह पैसा वहां– पर खर्च कर रहे हैं जहां सड़क टूटी है, फलड को वजह से तब ही हुई हैं । दूसरी जगह खर्च नहीं किया जा सकता

श्री मूल चन्द जैन : जौ 1.90 करोंड रुपया बचता है वह तो दूसरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर खर्च करना चाहिए ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक : फ्लड की वजह से जो सड़कें खराब –हुई हैं उनको ठीक कर रहे हैं । इन बारें मे इतना शोरगुल किया गया और कहा गया कि गैर–इन्साफी हो रही है । कोई जुल्म नही हो रहा है । बाबू मूल चन्द जी कौ इस बारे में कोई गिला नहीं होना चाहिए

श्री सभापति : अगर मिनिस्टर महोदय किसी डिस्ट्रिक्ट से डिस्किमिनेशन करेंगे तो फिर मैम्बर बोलेंगे ही । आपके लिए तो सारा हरियाणा एक डिस्ट्रिक्ट है और सारे डिंस्ट्रिक्टस आपके लिए बराबर हौंने चाहिएं ।

चौधरी' सतवीर सिंह मलिक : चेयरमैन साहब, यह जो अमांउन्ट था यह विशेष परपज के लिए सेन्ट्रल गवर्नमैट से सरकार को मिला था और उसी विशेष परपज के लिए यह खर्च किया जा रहा है । अब एक लाटरीज की बात आई । इसके बारे में बाबू मूल चन्द ने भी कहा और पहले भी 'यह बात हाउस में आई थी,

'यह सवाल उठा था कि लाटरीज कौ बन्द कर दिया जाए । लेकिन मैं यह बताना' चाहता हूं कि, यह निर्णय लिया गयी है कि जब तक दूसरे राज्यों में लाटरी चलं रही है यह बन्द न की जाए । हरियाणा, के अन्दर हमारी लाटरीज की इतनी सेंल नही होती । हमारे हरियाणा में तो 'कुल लाटरीज की जितनी टिकटें बिकती हैं' उसकी पाँच या दस परसैंन्ट ही यहां बिकती हैं । बाकी सारी सेल दूसरी स्टेटो में होनी है । चेयरमैन साहेब, अगर दूसरी स्टेटों 'में हमारी लाटरी की टिकटें बिकने से पन्द्रह बीस 'लाख रुपया स्टेट के खेजाने में आ जाए तो क्या खराब बात है । लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन कोई' स्कीम घाटे बोली होगी तो उसको खत्म कर दिया जाएगा और जब तक यह चलेगी' इसको बहुत अच्छी तरह' से और अच्छे ढंग से च नाया जाएगा । चेयरमैन साहब, एजुकेशन के सम्बन्ध में जो डिंमाड यहां पर पर रखी है, उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि यह एस्टीमेट कमेटी ने पास की है । श्री जैन जी में बोलते हुए लैण्ड एक्वीजीशन के बारे मेभी कुछ कहा, ' उनेकी बात ठीक है । मगर मैं उनको यह बत।. देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कोई 'लैर्ण्ड एक्वायर नहीं की है पर यह जो पैसा दिया जा रहा है यह तो सरकार आबलीगेशन के तहत अदालतों के हुकम की पालना कर रही है । जैन साहब ने वकीलों की फीस के बारे में अपनी स्पीच में बोलते हुए कहा । तो मैं उनको बता देना 'चाहता हूं कि यह तो पुरानी 'सरकार के कानून 'थे और हमने अब उन कानूनों को चेन्ज कर

दिया है और इतने ज्यादा पैसे 'चौधरी शमशेर सिंह के वक्त में जों वकीलों को दिये जातें रहे हैं, अब ' बन्द कर दिये गये हैं ।

चेयरमैन साहब, इसी तरह से स्वामी आदित्य वेश जी ने अपनी स्वीच में बोलते हुए कहा कि 88,17,000 रुपया केवल हिसार में ही खर्च किया जा रहा है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह सारे का सारा रुपया हरियाणा को खुशहाल करने के लिये ही सरकार खर्च कर रही है । मैं हाउस को एक ही यकीन दिला सकता हूं कि खुन पसीने की कनाई की जो एक एक पैसा होगा उस पैसे को किसी फिजूल काम के लिये खर्च नहीं किक जायेगा और न ही किसी फयूनरल पर खर्च होगा । बल्कि एक एक पैसा हरियाणा की खुशहाली के लिये ही खर्च होगा । इन शब्दो के साथ मैं औपका धन्यवाद 'करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके साथ साथ मैं हाउस अनुरोध करूंगा कि इस डिमांडज को पास किया जाए ।

Mr. Chairman : Now I will put the various Demands to the vote of the House.

Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 62,45,345 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 3—Home.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 95,63,270 be granted to the Governor to defray the charges

that will come in the "course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of .Demand No: 4:

—Revenue.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,19,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand -No. 7—Other Administrative Services.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 9,01,9S,480 be -granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 8—Buildings and Roads.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,95,68,095 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 9

—Education.

- The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come it the course of payment for the year ending

31st March, 1978 in respect of Demand No: 16

—Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 47,10,660 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 17

—Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 71,59,940 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 20—Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 92,31,841 be granted to the Governor to defray the charges that will coma in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 21—

Community Development.

The motion was carried.

Mr. Chairman : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1978 in respect of Demand No. 25—Loans and Advances by the State

Government.

The motion was carried.

वर्ष 1973–7 4 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

Mr. Chairman : The following Excess Demands Over Grants and Appropriations for the year 1973-74 will be deemed to have been read and moved .

That a grant of a sum not exceeding Rs. 6,625 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 12—Sales tax.

That a grant of **a** sum not exceeding Rs. 88,97,827 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 28—Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 23,96,788 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 39—Miscellaneous, social and Developmental Organisation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,19,42,196 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 43-44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial and Non-commercial.)

That a grant of a sum not exceeding Rs. 18,23,32,993 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 50—Public Works.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,49,622 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of Charges on Buildings and Roads Establishments.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 22,809 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in- respect of 70—Forest.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 7,25,866 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 96—Capital outlay on Industrial and Economic Development.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,86,01,892 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Asembly for the year 1973-74 in respect Of 98—Capital outlay on Multipurpose River Schemes.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 12,32,13,088 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 99—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works

(Commercial).

स्वामी आदित्यवेश (हथीन) : चेयरमैन साहब बड़ी आश्चर्य की बात है कि 1973– 74 का जो खर्चा है वह 1978 में पास करवाया जा रहा है । यह सारा खर्चा तो उस समय ही पास हो. जाना चाहिए था ह ह समझ नहीं आता कि यह खर्चा अब हम लोगो से क्यो पास करवाया जा रहा है जब कि यह पैसा पहले ही खर्च किया जा चुका है । सबसे पहले डिमांड नम्बर 1 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं जिसमें वर्ष के लिये 53,98,990 रुपये रखा गया था और जो खर्चा हुआ वह है 54,05,615 रुपये जिसके परिणाम स्वरूप 6,625 रुपये का अधिक खर्चा किया गया। इतना पैसा बिना इस हाउस से पूछे ही खर्च कर दिया गया और अब पूछ रहे हैं कि बताइये कि अब इसको पास कर दिया जाए? मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र का– रास्ता नहीं है, पहले भी ऐसे ही होता रहा है और अब भी वही तरीका अपनाया जा रहा है । चेयरमैन साहब, मैं कहूंगा कि यह जो इतना खर्व हुआ है, इसको अब हाउस में लाने की क्या आवश्यक्ता थी जबकि सारा पैसा रवर्च हो चुका है । गढ़े मुर्दे को उखाडने की क्या जरूरत थी? इसी प्रकार से डिमांड नम्बर 5 के बारे में है जिसमें पुराने हिसाब किताब के तरीके को ही बदल दिया गया और इस पर 1823.33 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च आ गया, जरा भी विचार नही किया गया कि किसान और मजदूर की खून पसीने की कमाई को कैसे खर्च किया जा रहा है । इसी नये मैं कहता हूं कि यह जो हिसाब किताब का नया तरीका अपना या गया है, यह उन गरीब मजदूर किसानों के

साथ बडा वे इन्साफ किया गया है । इसी प्रकार चेयरमैन साहब, आप डिमांड नम्बर 6 को गौर फरमाये । उसमें भवन तथा सड़क स्थापना पर खर्च की जाने वाली कुल राशि 2,65,00000 रुपये थी जबकि इस काम के लिये 2,75, 49, 622 रुपये खर्च हुये, इस तरह से 1049622 रुपये की राशि अधिक खर्च की गई और यह सारा खर्चा जैसा कि बता या– गया है टेलीफोनों के कारण, टेलीग्राफ प्रभारों की दरे बढ़ जाने के का रण किया गया है, यह बड़ी विडम्बना की बात है कि लोग कितने कितने टेलीफोन करते हैं और यूंके हम। रो गरीब जनता का औसा बरबाद किया जा रहा है । हमारा प्रान्त गरीब है । एक तरफ तो लोग भीख मांग मांग कर गुजारा करते हैं उनके पास रहने के लिये जगह नही है, उन्हें कपड़ा नहीं मिल पाता और दूसरी तरफ यहां पर लाखों रुपया टेलीफोनों की व्यवस्था पर खर्च किया जा रहा है । सरकार को जरूर इम तरफ ध्यान देना चाहिये ताकि गरीब जनता का पैसा यूंही ऐसे कामों पर बरबाद न हो । अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो मैं कहूंगा कि यह गरीब देश की जनता के साथ एक खिलवाड है, जो कि नहीं होना चाहिये । इसी तरह से मांग नं. 7 है इस पर भी 22809 रुपये अधिक खर्च कर दिये गये हैं । यह खर्चा जिला परिषदों को दूसरे विभाग में यानी वन विभाग में बदल देने की वजह से हुआ है । ये जितनी भी मांगे हैं मेरो दृष्टि में इनमें से एक भी उचित नहीं है । यह तो' लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है ।

इसी प्रकार से मांग नं. 8 में भी मैंने यह देखा है कि इसमें भी 725866 रुपये अधिक खर्च किये गये हैं । यह भी आश्चर्य की बात है । यह खर्चा इसलिये हुआ कि महालेखापाल द्वारा गश्त खर्चा शा मिल किया गया था । अगर हमारे महानुभाव खुद खून पसीना बहा कर कमाते तो उनको पता. लग जाता कि पैसा कैसे कमाया जाता हैं और इस तरह से पानी की तरह न बहाया जाता । मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सारी मांगे हैं ये, मेरी अन्तरात्मा के खिलाफ हैं और पैसे को इस तरह से पानी की तरह नहीं बहाया जाना चाहिये ।

वित्त मन्त्री (चौधरी सतवीर सिंह मलिक) : चेयरमैन साहब, लंबी बातें तो बजट पर डिस्कशन के समय होंगी लेकिन यदु तो पुरानी सरकार' द्वारा खर्च किए गए पैसे की डिमांडज हैं । इनके बारे में पहले ए 0 वी 0 से रिपोर्ट आई, फिर पी0 ए 0सी 0 ने उनका निंरीक्षण किया और अब यह रिपोर्ट हाउस के अन्दर आई हैं इसलिय इन्हें पास कर दिया जाए ।

Mr. Chairman : I will now put the Demands to the vote of the House.

Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 66,25 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 12—Sales tax.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 88,97,827

be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Lebislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 2,8—Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 23,96,7E8 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year1973-74 in respect of 39—Miscellaneous, social and Developmental Organisation.

chat a grant of a sum not exceeding Rs. 1,19,42,196 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 43-44—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial and Non-comme:-cial).

That a grant of, a sum not exceeding Rs. 18;21,12,993 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 50—Public

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,49,622 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of Charges on Buildings and Roads Establishments.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 22,809 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 70—Forest.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 7,25,866 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 96—Capital outlay on Industrial and Economic Development.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,86,01,892 be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 98—Capital outlay on Multipurpose River Schemes.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 12,32,13,088 be made to regularise charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1973-74 in respect of 99—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

The motion was carried .

Mr. Chairman : The house stands *adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 7th March, 1978.

17.03 बजे

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 7th March, 1978.)